● वर्ष-3
● अंक-241
रायपुर, शनिवार
18 मई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

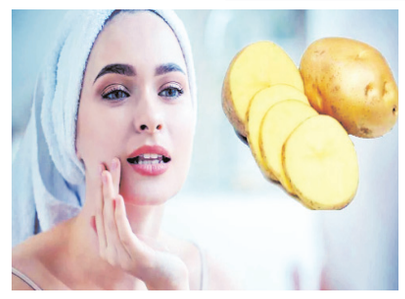

पेज-6›› आलू से निखारें चेहरे का ग्लो

दो दिन पहले सच क़बूला था और आज -स्वाति मालीवाल पर पलटवार

20 साल पुरानी कार्यकर्ता को भाजपा का एजेंट बताया गया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर चौतरफा हमला बोला। कुछ दिन पहले स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। हालांकि, अब आम आदमी पार्टी पर स्वाति मालीवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को भाजपा का एजेंट बता दिया। दो दिन पहले पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस में सब सच क़बूल लिया था और आज- यूटर्न

मालीवाल ने बिभव कुमार का नाम लिए बिना कहा कि ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज़ खोलूँगा। इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। उन्होंने कहा कि आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लडूँगी। जमकर करैक्टर असैसीनेशन करो, वक़्त आने पर सब सच सामने आएगा!

पार्टी ने केजरीवाल के निजी सहायक के खिलाफ राज्यसभा सदस्य मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। आप की यह टिप्पणी दिल्ली पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एक दिन बाद आई है। आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि वह पहले से मुलाकात का समय लिए बिना मुख्यमंत्री आवास पहुंची थीं और उनका इरादा केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाने का था। आतिशी ने कहा, आज एक वीडियो सामने आया है, जिसने मालीवाल के झूठ की पोल खोल दी है। अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा है कि उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और वह दर्द में थीं और उनकी शर्ट के बटन तोड़ दिए गए। सामने आया एक वीडियो बिल्कुल अलग हकीकत बयां करता है। प्राथमिकी के मुताबिक, कथित तौर पर कुमार ने मालीवाल को लात मारीं और सात से आठ बार थप्पड़ मारे। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि मालीवाल द्वारा रुकने को कहे जाने के बावजूद कुमार नहीं माने। आतिशी ने कहा कि वीडियो में मालीवाल आराम से ड्राइंग रूम में बैठी हुई और सुरक्षा कर्मचारियों को धमकाते हुए दिख रही हैं, और उनके कपड़े नहीं फटे थे। उन्होंने दावा किया, वीडियो में वह कुमार को धमकी देती दिख रही हैं। मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। मालीवाल ने केजरीवाल से मिलने की जिद की। वह राज्यसभा सदस्य हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम होता है। कुमार ने उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री व्यस्त हैं और उनसे मिलने में असमर्थ हैं।

प्रियंका गांधी से दुनिया की सबसे बड़ी एक्टरः राधिका

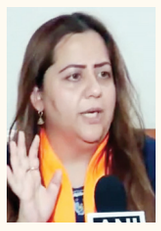

हाल में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली राधिका खेड़ा ने अब प्रियंका गांधी पर सीधे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से बड़ा एक्टर दुनिया में कोई नहीं है। अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना सबसे बुरा दौर देखा है, तो वह तब था जब कांग्रेस के यही महासचिव राज्य में पार्टी के प्रभारी थे। इसके साथ ही खेड़ा ने कहा कि उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का डायलॉग दिया लेकिन उनकी लड़ाई उनकी पार्टी की महिलाओं से है, मैं इसका जीता जागता उदाहरण हू। आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कहा कि आप और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां महिला विरोधी पार्टी हैं। अगर इतनी बड़ी घटना हुई है और संजय सिंह ने खुद इसे स्वीकार किया है, एफआईआर दर्ज की है तो फिर वो विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों घूम रहे हैं? यदि उनकी अपनी ही पार्टी का राज्यसभा सांसद मुख्यमंत्री कार्यालय में सुरक्षित नहीं है, तो वह महिला सुरक्षा के नाम पर वोट कैसे मांग सकते हैं?

विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगीः मुख्यमंत्री साय

कांग्रेस मतलब झूठ की फैक्ट्री, बहकावे में नहीं आएगी जनता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोगों से किए गए सभी वादे को पूरे करने के लिए हम लोगों को अभी बहुत राजस्व की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसकी व्यवस्था हम कर लेंगे। छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया है। यहां खनिज संपदा भरपूर है, वनोपज है, यहां की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं। हम सब मिलकर इतना सोर्सेस इकट्ठा कर लेंगे कि मोदी की गारंटी में जो भी वादे हैं, उसे पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक साक्षात्कार में उक्त बातें कही। 2014 में भाजपा के सबका साथ-सबका विकास और 2023 में मोदी की गारंटी स्लोगन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। इसे राष्ट्रीय भाजपा का स्लोगन बनने पर श्री साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जो कैंपेन यहां से शुरू होते हैं उसे देश की जनता तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। कांग्रेस द्वारा महिलाओं को सालाना एक लाख रुपए देने की बात पर सीएम साय ने कहा कि 2018 में कांग्रेस ने जनता से बड़े-बड़े वादे करके छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन 5 साल पूरा शासन चलाने के बावजूद भी इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया।

कांग्रेस, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। एक लाख की बात करें या पांच लाख की, अब यहां की जनता उनके किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है।

अब पाक भी कर रहा हमारी तारीफः राजनाथ

नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पर पाकिस्तानी नेता की सकारात्मक टिप्पणियों को उजागर करते हुए कहा कि इस्लामिक राष्ट्र भी भारत के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकास को स्वीकार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए लखनऊ में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि भारत 2027 तक संपत्ति के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर होगा। उन्होंने कहा कि हमारे एक ऐसे पड़ोसी जिन्होंने कभी भी हमारे देश के बारे में अच्छा नहीं बोला और आज उनके नेता बोल रहे हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश बन रहा है और पाकिस्तान आज भी पिछड़ा हुआ है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि दुनिया भर में भारत के प्रति धारणा बदल गई है। सभी देशों के नेता अब कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की है।

राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी (सपा) के रविदास मेहरोत्रा और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार सरवर मलिक से है। लखनऊ संसदीय सीट के लिए मतदान लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के साथ 20 मई को होना है। उनकी यह टिप्पणी पाकिस्तानी सांसद सैयद मुस्तफा द्वारा बुधवार को नेशनल असेंबली में अपने भाषण के दौरान भारत और पाकिस्तान की उपलब्धियों की तुलना करने के बाद आई है। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) के नेता ने कहा कि दुनिया चांद पर पहुंच रही है। लेकिन आज कराची में मासूम बच्चे खुले गटर में गिरकर मर रहे हैं। इसके अलावा, बाल्टीमोर स्थित पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी साजिद तरार ने भी भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें एक मजबूत नेता बताया, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। उन्होंने 2024 में भारत की बढ़त को स्वीकार करते हुए उम्मीद जताई कि पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता मिलेगा।

पाक अधिकृत कश्मीर में संसाधनों को लूटा जा रहा-विदेश मंत्रालय

पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने रिपोर्ट देखी है कि पिछले कुछ दिनों में वहां विरोध प्रदर्शन हुआ और उसमें कुछ लोग हताहत हुए। वहां जिस प्रकार की नीतियां चल रही हैं, संसाधनों को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है। यह विरोध उसका परिणाम है। जहां तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, लद्दाख, कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अर्धसैनिक रेंजर पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों द्वारा गोलियां चलाए जाने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल हो गए। मंगलवार को मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है।

खबरों के मुताबिक, पीओके में प्रदर्शनकारी गेहूं के आटे की ऊंची कीमतों और बिजली के बढ़े हुए दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

मोदी के बुलडोजर वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार

आरक्षण विरोधी मानसिकता दर्शाता हैः रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गुट के सहयोगियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है। एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आदित्यनाथ की वेबसाइट पर एक लेख का हवाला देते हुए दावा किया कि यह मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

वीडियो में, रमेश ने यह भी दिखाया कि लेख यूपी सीएम की वेबसाइट पर कहां है और कहा कि यह लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो सकता है। उन्होंने लेख के उन हिस्सों का भी हवाला दिया जो रमेश के अनुसार आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाते हैं।

रमेश ने कहा कि निवर्तमान प्रधानमंत्री ने आज कहा कि इंडिया गुट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है। देखिए कैसे योगी का बुलडोजर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है! जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि वह आरक्षण पर योगी के विचारों के कारण उनका समर्थन कर रहे हैं। यही उनके 400 पार के नारे के पीछे का राज है।

वह ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि संसद में 400 सीटों के बहुमत के साथ वह बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में संशोधन कर सकें और दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों से आरक्षण का अधिकार छीन सकें। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आईं तो अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी।

प्रमुख समाचार

केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र

नई दिल्ली। एक तरफ अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हैं और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। वहीं अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सभी पक्षों को अतिरिक्त हलफनामों के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। काफी दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि केजरीवाल चाहे तो जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। यह कार्रवाई कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी, विशेष लोक अभियोजकों के साथ, एक पूरक आरोपपत्र दायर करने के लिए दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे.

चारधाम यात्रा के संचालन के लिए 'मास्टरप्लान'- धामी

देहरादून। चारधाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि भविष्य में तीर्थयात्रा के सुचारु संचालन के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री में 'मास्टरप्लान' बनाया जाएगा। चार धामों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या के मद्देनजर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को एक बैठक की और उन्हें महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सुबह उन्होंने एक बार फिर अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर यमुनोत्री यात्रा का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी के बड़कोट पहुंचे। जायजा लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और पिछले वर्ष के मुकाबले यह संख्या लगभग दोगुनी हो गयी है जिसके कारण कहीं-कहीं श्रद्धालुओं को रोकना भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ''हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। धामों की क्षमता से दोगुने लोग आ रहे हैं। निकट भविष्य में हम गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान बनाएंगे.

सपा के नाराज विधायक मनोज पांडेय भी हो गये भाजपाई

लखनऊ। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे उसके विधायक मनोज पांडेय ने अभी तक तो पार्टी से दूरी बना रखी थी,और अब लोकसभा चुनाव के बीच पांडेय ने समाजवादी पार्टी एक बार फिर झटका दिया है है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और के रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 17 मई को उन्हें रैली में पार्टी में ज्वाइन करवाया। गौरतलब हो, समाजवादी पार्टी के नेता डॉ. मनोज कुमार पांडेय को विधानसभा चुनाव में हराने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मनोज पांडेय ने जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग और मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देकर सपा से दूरी बनाई। दो माह बाद 12 मई को चुनाव प्रचार के लिए जिले में आए गृहमंत्री अमित शाह डॉ. मनोज पांडेय के घर पहुंचे और लंच किया था, जिससकी राजनैतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई थी। गृहमंत्री से चर्चा के बाद सपा विधायक मनोज कुमार पांडेय के भाजपा का दामन थाम थामने से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह की राह आसान हो सकती है।

विशाखापत्तनम जासूसी मामले में दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को पाकिस्तानी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस जासूसी नेटवर्क के माध्यम से वर्गीकृत रक्षा जानकारी के रिसाव से जुड़े विशाखापत्तनम जासूसी मामले में एक अन्य प्रमुख व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मुंबई, महाराष्ट्र के निवासी अमान सलीम शेख पर औपचारिक रूप से एनआईए विशेष अदालत, विशाखापत्तनम में भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [यूए (पी) अधिनियम] की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है। शेख इस मामले में एक मुख्य आरोपी है, जिसमें भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए भारतीय नौसेना कर्मियों को हनी ट्रैप में फंसाने की पाकिस्तानी एजेंटों की साजिश शामिल है। शेख पर आरोप है कि उसने उस्मान नाम के एक संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट के निर्देशन में काम करते हुए इस साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनआईए की जांच के अनुसार, शेख को क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के माध्यम से मीर बालाज खान और अल्वेन सहित अन्य संदिग्ध पाकिस्तानी गुर्गों के साथ-साथ कई अन्य व्यक्तियों से भी धन प्राप्त हो रहा था।

चीन के व्यापारिक सौदों का आंकलन करना होगा-जयशंकर

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा फिल्टर के माध्यम से चीन के साथ व्यापारिक सौदों का आकलन करना होगा और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गतिरोध के बीच घरेलू निर्माताओं से अधिक सोर्सिंग करनी होगी। जयशंकर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया में हिंसा में वृद्धि, युद्ध और प्रतिबंधों के कारण रसद में व्यवधान और ईंधन, भोजन का संकट और उर्वरकों ने मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक परिपूर्ण तूफान पैदा कर दिया है। हालांकि जयशंकर ने अपने भाषण में चीन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने सवाल-जवाब सत्र के दौरान अपने उत्तरी पड़ोसी के बारे में भारत की चिंताओं को संबोधित किया, जिसमें व्यापारिक सौदों में प्राकृतिक सुरक्षा संवेदनशीलता को संबोधित करने की आवश्यकता भी शामिल थी। जयशंकर ने चीन के साथ व्यापार पर एक सवाल के जवाब में कहा कि जहां चीन का संबंध है, हम अभी भी इस देश में लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। हमने चीन के साथ काम करने वाले लोगों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया है.

केंद्रीय कर्मियों को मिलेगी 54 फीसदी महंगाई भत्ते की सौगात

जितेंद्र भारद्वाज

केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी संभव है। यानी पहली जुलाई से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 54 फीसदी पर पहुंच जाएगी। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता %डीए% मिल रहा है। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर, पचास फीसदी के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 50 प्रतिशत है। इसमें पहली जुलाई से चार फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। किसी महीने में कुछ प्वाइंट का अंतर आ जाता है, लेकिन जब जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का चार्ट बनेगा तो उसके आधार पर डीए/डीआर में कम से कम चार फीसदी की बढ़ोतरी होना तय है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी।

मार्च अप्रैल में मुद्रास्फीति ...

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संख्या पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2024 (अप्रैल, 2023 से अधिक) महीने के लिए 4.83 प्रतिशत (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमशः 5.43 प्रतिशत और 4.11 प्रतिशत है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के महीनों के लिए सीपीआई क्रमशः 5.10, 5.09 और 4.85 रहा है। शीर्ष पांच समूहों में, %कपड़े और जूते%, %आवास% और %ईंधन और प्रकाश% समूहों पर साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने से कम हुई है। मुद्रा स्फीति के अंतर्गत अप्रैल 2024 में सीपीआई (सामान्य) ग्रामीण क्षेत्र में 5.43 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 4.11 रहा है। संयुक्त प्रतिशत 4.83 है। इसी क्रम में उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) ग्रामीण क्षेत्र में 8.75 और शहरों में 8.56 प्रतिशत रहा है। संयुक्त प्रतिशत 8.70 है। मार्च 2024 में सीपीआई (सामान्य) ग्रामीण क्षेत्र में 5.51 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 4.14 रहा है। संयुक्त प्रतिशत 4.85 है। इसी क्रम में अप्रैल 2024 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) ग्रामीण क्षेत्र में 8.75 और शहरों में 8.56 प्रतिशत रहा है। संयुक्त प्रतिशत 8.70 है। मार्च 2024 के लिए शहरी क्षेत्र में सीएफपीआई 8.55 और शहरों में 8.41 प्रतिशत रहा है। संयुक्त प्रतिशत 8.52 है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूचकांक

अप्रैल 2024 के लिए सूचकांक की बात करें तो अप्रैल 2024 के लिए सीपीआई (सामान्य) ग्रामीण क्षेत्र में 188.5 प्रतिशत, शहरी क्षेत्र में 184.7 और संयुक्त प्रतिशत 186.7 रहा है। सीएफपीआई, ग्रामीण क्षेत्र में 188.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 195.4 प्रतिशत रहा है। संयुक्त प्रतिशत 191.2 रहा है। मार्च 2024 अंतिम के लिए सूचकांक की बात करें तो सीपीआई (सामान्य) ग्रामीण क्षेत्र में 187.8 प्रतिशत, शहरी क्षेत्र में 183.6 और संयुक्त प्रतिशत 185.8 रहा है। सीएफपीआई, ग्रामीण क्षेत्र में 187.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 193.4 प्रतिशत रहा है। संयुक्त प्रतिशत 198.8 रहा है।

इस तरह निकाली जाती है प्रतिक्रिया दर

साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ, एमओएसपीआई के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले चयनित 1114 शहरी बाजारों और 1181 गांवों से मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। अप्रैल 2024 के महीने के दौरान, एनएसओ ने 99.9 प्रतिशत गांवों और 98.5 प्रतिशत शहरी बाजारों से कीमतें एकत्र कीं, जबकि बाजार-वार कीमतें ग्रामीण के लिए 89.8 प्रतिशत और शहरी के लिए 93.2 प्रतिशत थीं।

दिसंबर 2023 में सूचकांक ...

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 0.3 अंकों की कमी दर्ज की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.22 प्रतिशत की कमी रही है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.15 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। यह संकलन, आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी होता है।

जनवरी में सीपीआई-आईडब्ल्यू 138.9 पर रहा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, श्रम ब्यूरो द्वारा देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है। यह सूचकांक 88 केंद्रों और अखिल भारतीय स्तर के लिए संकलित किया जाता है। इस सूचकांक को आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में काले हीरे की जमकर मची है लूट

बोरों में भरकर खुलेआम होती है तस्करी, लेकिन पकड़ी जाती है छोटी मछली

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ का हसदेव क्षेत्र हरे भरे पेड़ों और नदियों के लिए मशहूर है।एक और चीज इस क्षेत्र को अनोखा बनाती है।ये चीज है काला हीरा।जमीन के अंदर मौजूद इस काले हीरे के कारण इस क्षेत्र का नाम अदब से लिया जाता है।क्योंकि छत्तीसगढ़ के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान इसी काले हीरे का है।यही नहीं भारत की मिनी रत्न कंपनियों में भी इस काले हीरे की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता।लेकिन आज इस काले हीरे यानी कोयले की कालाबाजारी और चोरी के कारण शासन को करोड़ों का चूना लग रहा है।फिर भी आज तक कोयला चोरी रोकने के लिए कोई मास्टर प्लान ना तो कोल इंडिया के पास है और ना ही स्थानीय प्रशासन के पास।चिरमिरी क्षेत्र की बात करें तो बड़ी आसानी कोयला चोर अपना काम कर रहे हैं।लेकिन इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती।

कोलयांचाल क्षेत्र चिरमिरी में पुलिस ने अवैध कोयले से भरा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक में 100 बोरियों से भी ज्यादा अवैध कोयला लोड था।पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को भी अरेस्ट किया है। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि चिरमिरी खुली कोयला खदान के सीमावर्ती क्षेत्र से अवैध कोयला उत्खनन कर बोरियों में भरकर ट्रक में लोडकर पोड़ी बचरा ईट भट्ठे में खापने के लिए जा रहा था। चिरमिरी पुलिस ने बड़ी बाजार के पास घेराबंदी कर अवैध कोयला से भरे ट्रक को ड्राइवर समेत दबोचा।

चिरमिरी में अवैध कोयला का कारोबार दिन दूना

और रात चौगुना फल फूल रहा है।कोल माफिया बिना किसी डर के खदानों से कोयला चोरी करवाते हैं फिर इसे ईंट भट्टी और होटल में खपाया जाता है। चिरमिरी क्षेत्र में ही अवैध कोयले से सैकड़ों ईट भट्ठे बड़े पैमाने चल रहे हैं। लेकिन कार्रवाई सिर्फ ट्रक चालकों पर ही रही है। वहीं कोल माफिया बिना किसी कार्रवाई के बच निकलते हैं।इन कार्रवाई करने का काम खनिज विभाग और राजस्व का है।लेकिन अफसोस इनकी नींद कभी टूटती नहीं। वहीं तहसीलदार की माने तो कोल माफिया पर कार्रवाई की जा रही है।लेकिन हकीकत कुछ और ही है।

तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा ने कहा कोल के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है।किसी भी गुनाहगार को प्रशासन नहीं छोड़ेगा।

मीडिया के सामने भले ही अधिकारी कुछ भी बोले लेकिन जिस तरह से अवैध ईंट भट्ठों में कोयला पहुंच रहा है।उसे देखकर कहीं से ये नहीं लगता कि किसी भी कोल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। पुलिस और प्रशासन सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर अपना काम कर लेता है।लेकिन इस धंधे की बड़ी शार्क खुले समंदर में तैर रही है।जो किसी को दिखती ही नहीं ।वहीं एएसपी अशोक वाडेगावकर के मुताबिक कोल माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

एएसपी अशोक वाडेगावकर ने कहा हमको जो सूचना मिली है उस पर कोयला जब्त किया गया है। एसईसीएल से भी जांच की जाएगी कि यह कोयला कहां से चुराया गया है। आपके खदान से चुराया गया है कि कहीं अन्य और जगह से। अगर इस पर किसी प्रकार की दुविधाजनक बात बताई जाएगी तो खनिज अधिनियम के तहत खनिज विभाग को प्रकरण सौंप दिया जाएगा।

चिरमिरी कोल फील्ड में कोयले की कई खदानें हैं।एक भी खदान ऐसा नहीं है जहां कोयला की चोरी ना होती हो।हर साल हर खदान से लाखों रुपए का कोयला पार हो जाता है। यदि एक साथ इस चोरी के कोयले का आंकलन करें तो मामला करोड़ों में पहुंचेगा।फिर भी किसी भी एसईसीएल अधिकारी को आज तक इस ओर बड़ा एक्शन लेते नहीं देखा।वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन भी दावा करके अपना काम पूरा कर लेता है।ऐसे में कोल माफिया के दसों उंगली घी में नजर आती है।

धमतरी में भूमाफिया का कारनामा, मेन रोड के नाले को पाट कर बना दिया रोड

धमतरी। धमतरी के देमार गांव में भूमाफिया ने गजब का कारनामा किया है। यहां भूमाफिया ने कई एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की। इसके बाद प्लॉट कटिंग को मेन रोड से जोड़ने के लिए नाले को पाट कर एप्रोच रोड बना दिया। इसे लेकर बीते 24 जनवरी को टाउन एंड कंट्री विभाग ने एक नोटिस भी भेजा था। हैरानी की बात है कि नोटिस भेजने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर, भूमाफिया आज भी प्लॉट को डेवलप करने का काम कर रहा है।

दरअसल, धमतरी और रायपुर के बीच देमार गांव में मेन रोड के किनारे कई एकड़ कृषि जमीन पर सड़क बनाने और समतलीकरण का काम चल रहा है। यहां पर आवासीय प्लॉट काट कर बेचने की तैयारी भूमाफिया की तरफ से की जा रही है। लोगों का आरोप है कि यह काम पूरी तरह अवैध है। हद तो ये है कि इस प्लॉट को मेन रोड से जोड़ने के लिए नाले को पाट कर एप्रोच रोड बना दिया गया है। नाले के पट जाने से बरसात का पानी रुकेगा और पड़ोसी गांव तेलिन सत्ती में भयंकर जलभराव होगा।

भूमाफिया की इस मनमानी पर न तो देमार पंचायत को कोई आपत्ति है। न ही राजस्व विभाग कोई एक्शन ले रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से जनवरी माह में एक जमीन मालिक को एक नोटिस भेज कर औपचारिकता निभा दी गई है। तब से सभी जिम्मेदार खामोश हैं, लेकिन ग्रामीण इस मनमानी से चिंता में है। क्योंकि अभी भी जमीन मालिक का मुंशी इस जमीन पर मिट्टी पटवाने का काम करवा रहा है। इससे साफ है कि धमतरी में भूमाफिया को न कानून का डर है न प्रशासन का।

कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा मामले में शिकायत मिली है। जल्द कार्रवाई की जाएगी। कायदे से सबसे पहले पंचायत को इसके खिलाफ कदम उठाना था, लेकिन पंचायत की तरफ से जानकारी तक नहीं ली गई। मामले में सवाल पूछने के बाद पंचायत की तरफ से शिकायत की बात की जा रही है। भूमाफिया की इस हरकत पर ग्रामीणों ने आपत्ति जाहिर की है। वहीं, अन्य जिमेमेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पूरे केस मे कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।

वन वे व्यवस्था समाप्त, पार्किंग स्थल का कलेक्टर-एसपी ने किया निरीक्षण

जगदलपुर। जगदलपुर शहर में विगत कई दिनों से चल रही वन वे व्यवस्था को आखिरकार समाप्त कर दिया गया है। वन वे को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, पार्किंग व्यवस्था किस जगह संचालित किया जा सकता है, इन सभी बातों को जानने के लिए बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के साथ ही बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा भी मौजूद थे ।

बता दे कि शहर के बिजी मार्ग चांदनी चौक से एसबीआई चौक तक के मार्ग को व्यवस्थित यातायात सुविधा के लिए प्रायोगिक तौर पर वन-वे जिला प्रशासन द्वारा किया गया था, नागरिकों और व्यापारियों की सुविधाओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा वन-वे व्यवस्था को समाप्त किया गया। इस मार्ग में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शुक्रवार की सुबह कलेक्टर विजय दयाराम के. और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने सड़क पर जाकर निरीक्षण किया।

इसके अलावा व्यापारियों और नागरिकों से बातचीत भी की, इस दौरान कलेक्टर विजय ने कहा कि नगर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दो मार्गों को वन-वे किया गया था जिसका जनता ने बहुत सहयोग किया। व्यवस्था बनाने के लिए जो कमी पेशी रही उनका चिन्हांकन किया गया है, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के

लिए जनता के साथ व्यापारी भी सहयोग करें, उन्होंने कहा कि चांदनी चौक में सभी मार्गों के लगाए गए ट्रैफिक सिंगनल की टाइमिंग को व्यवस्थित की जाएगी और व्यवस्था बनाने के लिए चांदनी चौक में लगे बेरीकेट्स को अभी यथावत रखा जाएगा।

पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने कहा कि इन मार्गों में व्यवस्तम समय में अधिक भीड़ रहती है, सुगम यातायात के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, साथ ही इन मार्गों में दुकानों के सामने अव्यवस्थित तरीके से वाहन पार्किंग करने वालों पर कार्यवाही भी किया जाएगा, दोनों अधिकारियों ने मार्ग को पैदल चलकर मौका मुआयना किया और कन्हैया बीकानेर मिठाई दुकान के समीप स्थित नगर निगम के स्थल में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का भी जायजा लिया, पार्किंग स्थल में दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग जगह मार्क करने के भी निर्देश दिए।

तेंदुए का शिकार, पिता-पुत्र सहित तीन गिरफ्तार

कोरबा। कोरबा के कटघोरा वनमंडल के राहा बीट में तेंदुए का शिकार किए जाने के मामले में वन अमले की टीम ने तीन ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण की बछड़े को तेंदुए ने मार गिराया था जिससे आक्रोश में आकर बछड़े में जहर मिला दिया गया था जिसे पुन: खाने से तेंदुए की मौत हो गई थी और उसके अंगों को काटकर ले गए थे। इस मामले में तीनों ग्रामीणों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।

कटघोरा वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शिकार के मामले में तीन लोगों को भले ही गिरफ्तार कर लिया है लेकिन देर रात तक इस मामले में तेंदुए के प्रमुख अंगों को वन हमले की टीम बरामद नहीं कर पाई है। कटघोरा वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत ने बताया कि वन विभाग की टीम अभी मामले की जांच में जुटी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही तेंदुए के अंगों को भी बरामद कर लिया जाएगा। कटघोरा वनमंडल के चौतमा रेंज के राहा बीट के अंतर्गत आने वाले कक्ष क्रमांक 25 में बुधवार की सुबह लगभग 11 बजे एक तेंदुए को मृत अवस्था में ग्रामीणों ने देखा था। जहां तेंदुए की मौत की सूचना पर वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे जहां शिकारियों ने तेंदुआ का शिकार किया था और उसके महत्वपूर्ण अंगों को काटकर ले भागे थे।

मामला सामने आने के बाद आला अधिकारियों

के निर्देश पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया था लेकिन रात होने की वजह से कार्यवाही नहीं हो पायी थी। गुरुवार की सुबह लगभग 5 बजे डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया गया जहां घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक बछड़ा मरा पाया गया। जिसे किसी वन्य प्राणी ने आधे से अधिक भाग खा लिया था। डॉग स्क्वाड की टीम आगे बढ़ते हुए घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर ग्राम भवरदा निवासी गोविंद के घर जा धमका और फिर क्या था वन अमले की टीम ने गोविंद सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके बछड़े को किसी वन्य जीव ने हमला कर मार दिया था जिसकी वजह से वह आक्रोशित था और उसने अपने मृत बछड़े में फोरेट मिला दिया और जब तेंदुआ पुन: बछड़े का मांस खाने पहुंचा तो मांस खाने के कुछ ही क्षणों बाद उसकी मौत हो गई जिसके बाद गोविंद सिंह व लाल सिंह और दर्रीपारा निवासी राम प्रसाद तेंदुए के अंग को काटकर ले भागे थे।

जंगल में एक साथ दिखे चार बाघ सड़क पार करते हुए कैमरे में कैद

कोरबा। कोरबा जिले के पाली वन परिक्षेत्र के डीजे सांगा में बाघ दिखने का दावा किया गया है। सड़क पार करने के दौरान चार की संख्या में बाघ और शावक नजर आए हैं जिनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाने में वन विभाग लगा हुआ है।

वायरल वीडियो के संबंध में ग्रामीणों ने इस बात का उल्लेख किया है कि ग्राम पहाड़ गांव निवासी विनोद कुमार आयम के घर शादी थी। जिसमें शामिल होकर रात 9.30 बजे ग्राम पंचायत जेमरा के सरपंच भंवर सिंह उईके व ग्रामीण दशरथ सिंह राज मोटर साइकिल से लौट रहे थे। इसी दौरान रामटॉक जंगल के छिंदपहरी एवं सपलवा रोड के तिराहे के पास बाघ दिखे। दूर से हार्न बजाने के बावजूद वह टस से मस नहीं हुये। यहां से दोनों व्यक्ति अपने गांव आकर पंचायत के लोगों को बाघ के बारे में जानकारी दी।

ग्रामीणों की माने तो इस इलाके में कई बार बाघ को देखा गया है जो घर के आंगन में बकरी और मवेशियों को अपना शिकार बन चुके हैं। वन मंडल परिक्षेत्र में दिनों दिन बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसके चलते ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है इसकी सूचना वन विभाग को भी दी जा चुकी है।

इस संबंध में पूछे जाने पर कटघोरा डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि खबर की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटाया जा रहा है, इसके बाद ही वास्तविकता का पता चल सकेगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कार्यपालन अभियंता के बंगले में एसीबी ने मारा छापा

कोंडागांव। कोंडागांव में एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर ने छापेमार कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता टी आर मेश्राम को पचास हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जल संसाधन विभाग का यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले का मामला अभी न्यायालय में लंबित है जिसमें तत्कालीन कार्यपालन अभियंता आर बी सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूर्व के मामले का निपटारा अभी हुआ ही नहीं था कि तत्कालीन कार्यपालन अभियंता आर बी सिंह की जगह आए हुए कार्यपालन अभियंता टी आर मेश्राम को आज एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर की टीम ने 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अभी कार्रवाई कर रही है जल्द ही उनके द्वारा मामले का ब्यौरा दिया जाएगा।

अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन का एक्शन

कांकेर। अवैध रेत उत्खनन को लेकर आखिरकार खनिज विभाग की नींद टूटी है। चारामा के भिरौद घाट में चेन माउंटेन से रेत निकाल रहे मशीन को जब्त किया गया है। लेकिन इस कार्रवाई में भी सोचने वाली बात ये है कि चारामा क्षेत्र के तेलगुड़ा, माहुद, मचानदूर समेत सभी खदानों पर चैन माउंटेन से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने सिर्फ भिरौद घाट में छापामार कार्रवाई की है। रेत खदान में हुई इस कार्रवाई से सभी रेत खदान में हड़कंप मच गया है।आपको बता दें कि दोपहर को एसडीएम प्रशासनिक अमले के साथ भिरौद घाट पहुंचे और रेत मशीन पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ये रेत माफिया बिना फिट पास के सैकड़ों घन मीटर रेत का खुदाई नियमों का ताक पर रखकर चैन माउंटेन लगाकर खुदाई कर रहे हैं। एसडीएम राहुल रजक ने कहा छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। एक चैन माउंटेन और 4 हाइवा रेत से भरा हुआ था।

जंगल बने प्राकृतिक प्रयोगशाला दुर्लभ जीवों को देखने का मौका

कोरबा। गर्मियों में एग्जाम खत्म होते ही लोग अपने घर निकल जाते हैं लेकिन कोरबा के जंगलों में एक ऐसा प्रयोग हो रहा जिसमें अलग- अलग कॉलेज के बच्चे किताबों में पढ़ने वाले ज्ञान का प्रयोग जंगलों में सीख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में किंग कोबरा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमे वन विभाग के मार्गदर्शन में नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की अध्ययन दल जंगलों के अलग-अलग हिस्सों में इस दुर्लभ जीव किंग कोबरा और उनके रहवास पे अध्ययन कर रही हैं। ऐसे में कोरबा वन मंडल एवं नोवा नेचर वेलफेयर सोसइटी द्वारा प्राकृतिक प्रयोगशाला के तर्ज पर कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चों को इस प्रोजेक्ट टीम के साथ जंगलों में विभिन्न विषयों को सीखने का मौका दिया, पिछले कुछ महीनो में राज्य के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले जूलॉजी, बॉटनी, मैनेजमेंट आदि विषयों के छात्र आये और किंग कोबरा टीम के साथ कई विषयों को जंगलों में सीखा जिसमें जीवों की पारिस्तिथिकी, वन्यजीव संरक्षण और उसमे विज्ञान का महत्व, वन्यजीवों और उनके रहवास में सम्बन्ध आदि।

दसवीं की परीक्षा में फेल होने से आहत छात्रा ने लगाई फांसी

दुर्ग। दुर्ग में दसवीं की परीक्षा में फेल होने से आहत छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है जिसके बाद पुलिस मर्ग कायम कर जांच के में जुट गई है। दुर्ग के उरला आईएचएसडीपी आवास में रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा धनेश्वरी खरे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धनेश्वरी सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा थी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद से ही धनेश्वरी उदास रहती थी मृतका दसवीं के बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी विषय में वो फेल हो गई थी उसके माता-पिता दोनों मजदूरी करते हैं। घर में छात्रा अकेली थी लेकिन जब उसका भाई घर पहुंचा तो उसने देखा कि धनेश्वरी की फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। जिसके बाद उसने तुरंत पास पड़ोस के लोगों के साथ पुलिस को सूचना दी फिलहाल पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है परिजनों ने पुलिस को बताया है कि दसवीं की परीक्षा में फेल होने के बाद से ही वह परेशान और उदास रहती थी। पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है।

शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो एटीएम में चोरी करने पहुंचा युवक

कोरबा। कोरबा में एटीएम में हुई तोड़फोड़ और चोरी के प्रयास में घटना के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सीसीटीवी फुटेज क आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि शराब के लिए पैसे नहीं मिलने के कारण उसने एटीएम में चोरी की घटना का अंजाम देने का प्रयास किया। यह पूरा मामला बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत कोनकोना स्थित एटीएम में सेंधमारी कर पैसों की चोरी का असफल प्रयास का है। कोरबा की बांगो पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है,जिसने कोनकोना स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम में सेंध मारी कर घुसा था मामला सामने आने के बाद बैंक मैनेजर ने पुलिस से शिकायत बांगो थाना पुलिस से की थी। सीसीटीवी में कैद वीडियो के आधार पर वारदात के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी का नाम सोम प्रकाश धनवार है,जो उमानीदांड का निवासी है, शराब पीने के लिए पैसे नहीं होने पर वह सेंध मारी कर एटीएम में घुसा था और हथियार से एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया था।

चुनावी मौसम में गन्ना किसानों की गुहार, सियासी वादे वास्तविकता से दूर

वी. एम. सिंह

देश 18वीं लोकसभा के लिए सांसद चुनने में लगा हुआ है। हर पार्टी लुभावने वादों से मतदाताओं को रिझाने में लगी है। मगर कृषि प्रधान इस देश में कोई भी पार्टी किसानों के संकट दूर करने की बात नहीं करती। कुछ पार्टियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की बात की है, पर फसल की लागत कैसे तय की जाएगी, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब पांच करोड़ गन्ना उत्पादक किसान परिवार हैं और देश की आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा गन्ना उगाने से जुड़ा है, पर उनकी गुहार कोई नहीं सुनता।

हालांकि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की सभा में प्रधानमंत्री ने गन्ना की बात की और कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, जिससे किसानों का जीवन बहुत बेहतर हो गया। गन्ना किसानों का जो भी भला हुआ है, वह उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने गन्ने का रेट (एसएपी) निर्धारित कराने का अधिकार दिया, नहीं तो किसानों को एक तरफ केंद्र द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य मिलता और दूसरी तरफ मिल द्वारा 1996 से 2020 तक दी गई पर्चियों के कारण किसानों को प्रति एकड़ लगभग चार से पांच लाख रुपये मिलों को लौटाना पड़ता, क्योंकि हर पर्ची पर लिखा था कि लेन-देन सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर होगा। मिल मालिक राज्य और केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ना रेट का फर्क हर किसान से वसूलते।

यूपी में गन्ना रेट की लड़ाई 1996-97 के गन्ना सत्र में शुरू हुई, जब यहां भाजपा व बसपा की सरकार थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिल मालिकों की रिट याचिका?में 11 दिसंबर,1996 को आदेश देकर राज्य सरकार को गन्ना का रेट तय करने से मना कर दिया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी। संविधान पीठ के फैसले से राज्य सरकार को रेट तय करने का अधिकार मिला। संविधान पीठ ने पांच मई, 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की रिट याचिका 1997 को बरकरार रखा, जिसमें किसानों को विलंब से गन्ना मूल्य मिलने पर ब्याज देने को कहा

?था। सरकार ने ब्याज देने का आदेश तो जारी किया, लेकिन जब किसानों को ब्याज का पैसा नहीं मिला, तो किसान मज़दूर संगठन ने 2006 में रिट याचिका दाखिल की और किसानों को 1996 से अब तक का ब्याज दिलवाने की गुजारिश की।

किसानों ने अंतर मूल्य देने के लिए रिट याचिका दाखिल की। एक सोसाइटी एक रेट और एक मिल एक रेट के आधार पर पेराई सत्र 2009-10 में राज्य सरकार द्वारा घोषित 165 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय आखिरी पर्ची पर 260 रुपये मिला। 2011-12 के गन्ना मूल्य एवं विलंब पर ब्याज देने के लिए रिट याचिका 6429/2012 दाखिल हुई थी। एक मई, 2024 को चार याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी थीं। सरकार ने अपने जवाब में ब्याज एवं अंतर मूल्य देने से इन्कार?कर दिया। मिल मालिकों के अधिवक्ता ने कहा, अगर किसानों को 1996 से ब्याज देंगे, तो मिलें बंद हो जाएंगी। हाईकोर्ट ने सरकार से 1996-97 से आजतक का गन्ना भुगतान, जिसमें विलंब होने पर ब्याज का भुगतान भी शामिल है, का पूरा ब्योरा मांगा है। अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

वर्ष 2014 में जब हाईकोर्ट ने भुगतान के विलंब पर ब्याज देने का आदेश दिया, लेकिन मिल मालिकों की अर्जी पर तत्कालीन सरकार ने 2012-15 तक का ब्याज माफ कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने 2017 में खारिज कर दिया और गन्ना आयुक्त को चार महीने में इसका फैसला करने के लिए कहा। जब गन्ना आयुक्त ने एक साल तक कुछ नहीं किया, तो उच्च न्यायालय ने गन्ना आयुक्त को तलब किया, उसके बाद 2019 में आयुक्त ने फैसला दिया कि घाटे में चल रही मिलें सात फीसदी और बाकी मिलें 12 फीसदी ब्याज देंगी। आज तक किसानों को यह पैसा नहीं मिला है। दिसंबर 2022 में जब हाईकोर्ट ने कड़ा रुख लिया, तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी। यह अर्जी भी सरकार ने उस याचिका में लगाई, जिसमें सरकार द्वारा गन्ना भुगतान के विलंब पर ब्याज माफ करने के अधिकार को चुनौती दी थी। राजनीतिक पार्टियां इस तरह वादे करती हैं, पर वास्तविकता कुछ और होती है। क्या किसानों को अंतत: अपनी नई पार्टी बनाने से ही न्याय मिलेगा?

संक्षिप्त समाचार

आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक पांडुरंग मोघे का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक पांडुरंग शंकरराव मोघे का गुरुवार रात निधन हो गया। उन्होंने 93 साल के उम्र में राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शोक संदेश में लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक पांडुरंग शंकरराव मोघे जी के निधन का दु:खद समाचार मिला। उन्होंने समूचे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विचारों को स्थापित करने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनकी स्मृति सदैव अमर रहेगी। सीएम साय ने कहा कि पांडुरंग शंकरराव मोघे धमतरी जिले में लंबे समय तक संघ के प्रचारक रहे। आपातकाल के दौरान सागर जिले में सत्याग्रह करते हुए जेल भी गए। रायपुर में संघ कार्यालय निर्माण के समय उनकी महती भूमिका रही। गायन कला में उनकी विशेष रुचि थी। उनकी स्मरण शक्ति भी लाजवाब थी। सादा जीवन उच्च विचार को अंगीकार कर अपना सर्वस्व जीवन जीने वाले मोघे का निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है।

अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

रायपुर। रायपुर जिले में अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही अवैध रेत मामले में 310 और मुरम भंडारण मामले में 135 हाईवा को जब्त किया गया है। रायपुर कलेक्टर के निर्देशन पर सीएमओ और तहसीलदार ने मंदिर हसौद में कार्रवाई की है। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार पर मंदिर हसौद में सीएमओ मंदिर हसौद और तहसीलदार की उपस्थिति में अभिषेक गुप्ता का एक एकड़ और पिंटू ब्रह्मा का दो एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग को हटाते हुए कार्रवाई की गई है। साथ ही ग्राम नकटा में शासकीय भूमि पर लगभग 310 हाईवा अवैध रेत और 135 हाईवा मुरम भंडारण पर कारवाई करते हुए जब्त किया गया। वहीं रायपुर अटल एक्सप्रेसवे पर खुले अवैध प्लॉटिंग के रास्ते को बंद किया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने जिले के राजस्व अमला और नगर निगम जोन कमिश्नरों की बैठक लिए। इसमें जिले में अवैध प्लॉटिग और अतिक्रमण पर रोक लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।

रीपा में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी के गठन का कौशिक ने किया स्वागत

रायपुर। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने रीपा में भ्रष्टाचार की जांच के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा मुख्य सचिव और अन्य सचिवों की जांच कमेटी बनाए जाने का स्वागत किया है। कौशिक ने सोशल मीडिया में किए अपने पोस्ट में कहा कि जिस किसी ने भी छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनता का पैसा खाया है, ऐसे किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा। धरमलाल कौशिक ने सोशल मीडिया में किए अपने पोस्ट में विधानसभा में रीपा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने जाने का जिक्र करते हुए साय सरकार के जांच कमेटी के गठन का स्वागत किया है। जांच शुरू होने की अखबार में छपी खबर का क्लिप शेयर करते हुए मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन में भ्रष्टाचार का खेल नहीं होने और किसी भी अपराधी को नहीं बख्शे जाने की बात कही है।

भिलाई का सुपेला अंडरब्रिज पब्लिक के लिए खुला, आवाजाही शुरू

भिलाई। शहर के सुपेला चौक के पास

अंडरब्रिज बनाने का काम रेलवे ने लगभग 3 साल पहले शुरू किया था, जो अब पूरा हो चुका है। सुपेला अंडरब्रिज का आज रेलवे के डीआरएम संजय कुमार ने नारियल फोड़ कर उद्घाटन किया। जिसके बाद अंडर ब्रिज से आवाजाही शुरू हो गई है। रायपुर रेल मंडल के डीआरएम संजीव कुमार ने बताया, आज हम भिलाई के सुपेला पहुंचे। जहां पहले तो अंडरब्रिज का मुआयना किया। इसके बाद 32 करोड़ की लागत से बनाए गए सुपेला अंडरबब्रिज का उद्घाटन किया। देश में हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए रेलवे फाटकों को हटाया जा रहा है। रेलवे फाटकों की जगह पर अंडरब्रिज या फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। डीआरएम संजीव कुमार ने कहा 3 साल पहले सुपेला रेलवे फाटक को भी बंद किया गया था, जिसके बाद अंडरब्रिज का काम शुरू किया गया, जो कुछ दिनों पहले ही पूरा हुआ है। यह अंडरब्रिज सुपेला की तरफ 85 मीटर और पावर हाउस की ओर 95 मीटर लम्बा है। इसकी चौड़ाई 8।5 मीटर हैं। इस अंडरब्रिज के शुरु होने से अब सुपेला से सेक्टर एरिया की ओर या दुर्ग की ओर लोग आराम से आना जाना कर सकेंगे। भिलाई के सभी अंडरब्रिजों में से सुपेला अंडरब्रिज सबसे खूबसूरत है। इसमें अभ्यारण से लेकर तारामंडल तक का एहसास यहां से गुजरने वाले लोग कर सकेंगे।

भाजपा के मंत्रियों और विधायकों ने ओडिशा और झारखंड में झोंकी ताकत

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री और पदाधिकारी इन दिनों ओडिशा और झारखंड में डेरा जमाये हुए हैं। वहां पर पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धि बताने के साथ ही ओडिशा-झारखंड दोनों राज्य सरकारों की कमियां गिना रहे हैं। अलग-अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बरगढ़ और संभलपुर, वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कांटाभांजी लोकसभा क्षेत्र, मुख्यमंत्री विजय शर्मा बरगढ़ और मयूरभंज, मंत्री ओपी चौधरी बरगढ़ और सुंदरगढ़, मंत्री टंकराम वर्मा सुंदरगढ़, पूर्व मंत्री राजेश मूणत भुवनेश्वर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा में कमान संभाले हुए हैं।

डबल इंजन की सरकार चुनने का मौका : अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी से बेहतर विकल्प ओडिशा के लिए कोई और नहीं है क्योंकि जिस प्रकार पिछले 25 वर्षों से ओडिशा का शोषण किया गया है। उसके विदाई का ओडिशा की जनता ने मन बना लिया है। ओडिशा की जनता इस चुनाव को भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाने के सुनहरे अवसर के रूप में देख रही है।

ओडिशा की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए भाजपा जरुर : शर्मा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ओडिशा की तकदीर एवं तस्वीर बदलने के लिए भाजपा जरूरी है। आरोप लगाते हुए कहा कि नवीन पटनायक सरकार का रवैया ओडिशा के विकास के लिए निष्क्रिय है। पटनायक सरकार केवल सत्ता को अपना उद्देश्य मानती है सेवा को नहीं।

केंद्र की हर कल्याणकारी योजनाओं में अड़ंगा लगा रही ओडिशा सरकार

वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पटनायक सरकार ने पिछले ढाई दशकों से प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रखा है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र की हर कल्याणकारी योजनाओं में अड़ंगा लगाकर ओडिशा को शोषित बनाकर रखा है। अब ओडिशा की जनता ने प्रदेश की उन्नति के लिए भाजपा को जिताने का संकल्प कर लिया है।

झारखंड में खत्म होगी पिता-पुत्र के भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स : भूपेंद्र सवन्नी

छत्तीसगढ़ भाजपा उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने कहा है कि झारखंड में इस बार के चुनाव से राज्य को पिता-पुत्र के भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स से मुक्ति मिलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के संसाधनों की जैसे खुली लूट मचाई है, उससे जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। यह लोकसभा चुनाव सिर्फ विकसित भारत के संकल्प का चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और लालफिताशाही से मुक्ति दिलाने का भी चुनाव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब चुनाव में अपनी हार तय मानकर नये बहाने खोजने लगी है।

झारखंड में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे धरमलाल

झारखंड के जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशी विद्युतवरण महतो के पक्ष में घाटशीला विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा से वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू एवं घाटशीला विधानसभा के समस्त ऊर्जावान कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संजय श्रीवास्तव ने रांची में संभाली चुनाव प्रचार की कमान

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने झारखंड के रांची लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। बुधवार को उन्होंने सुखदेव विधानसभा के सुखदेव नगर मंडल, अपर बाजार मंडल, लोअर बाजार मंडल के शक्ति केंद्र, मंडल प्रभारी, संयोजक एवं सह संयोजकों की बैठक ली। शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ चर्चा कर उन्होंने बूथ समितियों के माध्यम से घर-घर पर्ची, प्रचार सामग्री भेजते हुए जनसंपर्क अभियान तेज करने की अपील की। इसके साथ ही 19 और 20 मई को मतदान पर्ची वितरण अभियान का शुभारंभ लोकसभा के सभी मंडलों में किए जाने के विषय पर चर्चा हुई।

पटनायक ने ओडिशा में कुशासन का कीर्तिमान स्थापित किया : पुरंदर

प्रदेश भाजपा सह प्रभारी एवं रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने संबलपुर में एक चुनावी सभा में आरोप लगाते हुए कहा कि नवीन पटनायक ने ओडिशा में कुशासन का कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र की योजनाओं पर बाधा अटकाने एवं मोदी सरकार की योजनाओं पर अपने नाम की लीपापोती करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। ओडिशा को हर मोर्चे पर पिछड़ा हुआ बना दिया है। तमाम खनिज संसाधन, मेहनतकश प्रदेशवासी, केंद्र सरकार द्वारा निरंतर भेजी जा रही भारीभरकम सहायता राशि का भी पटनायक सरकार ने दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा नो सीएम है नवीन बाबू।

भूपेश बघेल के एक्स पोस्ट पर राधिका खेड़ा ने कसा तंज

महिलाओं का सम्मान आप और कांग्रेस कितना करती है इसका उदाहरण मैं हूं

रायपुर। राधिका खेड़ा ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा के इस आरोप के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब बवाल हुआ। वहीं भाजपा में आते ही खेड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक्स पोस्ट पर तंज कसा है। बघेल पर तंज कसते हुए खेड़ा ने कहा कि आपने युवाओं को पीएससी फर्जीवाड़ा और बेरोजगारी भत्ते के मामले में ठगा है। आगे कहा कि महिलाओं का सम्मान आप और आपकी पार्टी कितना करती है इसका उदाहरण मैं ही हूं। कका रायबरेली की भोली-भाली जनता को बहकाने की कोशिश न करें।

राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, छत्तीसगढ़ में युवाओं को पीएससी फर्जीवाड़ा और बेरोज़गारी भत्ते के मामले में आपने ठगा। महिलाओं को रू. 500 देने का वादा करके नही दे पाए, और महिलाओं का सम्मान आप और आपकी पार्टी कितना करती है इसका उदाहरण मैं ही हूं! रायबरेली की भोली भाली जनता को बहकाने की कोशिश न करें कका। दरअसल, भूपेश बघेल को रायबरेली का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। रायबरेली से प्रत्याशी राहुल गांधी के पक्ष में भूपेश बघेल जमकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं 16 मई को भूपेश बघेल रायबरेली क्षेत्र में किये गए प्रचार को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेगी, युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देगी, सभी युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा, महिलाओं के खातों में रू. 1 लाख आएंगे। इंडी गठबंधन की सरकार आम देशवासियों की सरकार होगी, सबको न्याय देगी। जिसपर अब राधिका ने पलटवार किया है।

निगम ने कार्य की अनुमति दे दी और महापौर को मालूम नहीं

रायपुर। रायपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली को देखते हुए अब तो वाकई कुछ भी कहा जा सकता है। जिस गार्डन के व्यावसायीकरण को लेकर विरोध हो रहा है उसके बारे में यह नहीं मालूम कि जमीन आरडीए की है नगर निगम की। महापौर कहते हैं कि कार्य की अनुमति किसने दी यह भी नहीं मालूम? पार्षदों के साथ विरोध स्वरूप धरने पर भी बैठ गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अधिकारियों के मनमर्जी यहां काम शुरू हो गया। दरअसल श्रीगहोई वैश्य समाज के लोग विरोध में उतरे तब मामला गरमाया। देखें क्या परिणाम निकलता है।

जानकारी के मुताबिक, राष्ट्र कवि डा. मैथिलीशरण गुप्त के नाम से बने तेलीबांधा उद्यान को उखाड़ा जा रहा है और व्यवसायीकरण के उपयोग में लाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर श्रीगहोई वैश्य समाज के लोग विरोध

कर रहे हैं। उनके साथ वहां के स्थानीय लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इसकी जानकारी मिलने पर महापौर एजाज ढेबर और उनके एमआइसी मेंबर भी मौके पर पहुंचे। उन्होने भी विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दे दिया।

महापौर ने कहा कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। निगम इस गार्डन का कैसे व्यवसायीकरण कर रहा है। मैं इसे व्यवसायिक उपयोग के लिए विकसित नहीं करने दूंगा। इसे लेकर नागरिकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि जब महापौर को ही मामले की जानकारी नहीं है तो निगम द्वारा कार्य के लिए अनुमति कैसे दी गई। उससे भी बड़ी बात यह रही कि महापौर खुद धरने पर बैठ गए।इसके बाद सवाल उठा कि महापौर के कार्यकाल में ही तो गार्डन को निजी हाथों में सौंपा गया है। इसे लेकर एमआइसी सदस्यों ने कहा कि हमने अनुमति नहीं दी, शासन का ही प्रस्ताव था, हालांकि कुछ स्थानों के लिए था। जानकारी के मुताबिक यह उद्यान आरडीए की संपत्ति है।

इसे मेंटेन करने आरडीए ने निगम को और निगम ने वैश्य समाज को दिया हुआ है। यहां समाज कवि की प्रतिमा लगातार हर वर्ष सभाएं आयोजित करता है। बीते दो दिनों से यहां कुछ मशीनें लगाकर निर्माण कार्य शुरू कर किया जा रहा था। इस दौरान कुछ पेड़ भी काटे गए। इसके बाद वैश्य समाज के लोग विरोध में उतर आए। बहरहाल मामला गरमाया हुआ है।

राजस्व न्यायालयों में लगा फाइलों का अंबार

- अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी से सीमांकन से लेकर नामांकन तक के काम अटके

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनावी ड्यूटी में अधिकारियों के लगे होने की वजह से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। तहसील से लेकर संभागीय न्यायालयों तक में हजारों मामले महीनों से लटके पड़े है, जिनका कब का निराकरण हो जाना था। फाइलों के लटके होने की वजह से पक्षकार कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

जिलों के हिसाब सबसे ज्यादा मामले रायपुर जिले में अटके है। जिले में करीब 11 हजार मामले पेंडिंग पड़े हैं। लंबित राजस्व प्रकरणों की नियमित समीक्षा नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। पूर्ववर्ती सरकार में भी यही स्थिति थी। नई सरकार बनने के बाद मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। राजस्व दफ्तरों में पैसे लेन-देन की शिकायतों को देखते हुए आए दिन कलेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर कड़ी फटकार भी लगाते हैं। उसके बावजूद जमीन संबधी मामले कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं।

तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे भाटागांव के छोटू लाल साहू बताते हैं कि एक साल से मेरी जमीन को कब्जा किया गया है, जिसको मैं लेकर में लगातार तहसील कार्यालय आ रहा हूं, लेकिन यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नामांकन के लिए डेट पर डेट दे रहे

हैं, लेकिन अब तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की बात अधिकारी कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, तो सर्वर लो जैसी समस्याएं सामने आती है, जिसको लेकर हम लगातार तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं।

कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि चुनावी व्यवस्था के चलते कोई प्रकरण नहीं रुके हैं। सभी तरीके से राजस्व के काम में तेजी लाई है। इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एसडीएम नंदकुमार चौबे और तहसीलदार पवन कोसरे का कहना है कि कहीं कोई काम नहीं अटका है। केवल कुछ परसेंट काम रुका हुआ है। हम लोगों ने अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया था, इसका थोड़ा प्रभाव पड़ा है।

बता दे कि पिछले कई सालों से तहसील कार्यालय लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं। आज भी कई ऐसी फाइल है, जिनका निपटारा किए बिना ही बंद कर अलमारियों में रख दिया गया है। मामले में कलेक्टर सहित तमाम राजस्व अधिकारी सही तरीके से काम होने का हवाला देते हैं। अब आगे देखना होगा लगातार राजस्व अधिकारियों की बैठक के बाद जमीन से संबधित कितने काम पूरे होंगे।

संपत्ति के मूल्यांकन में नुकसान बर्दाश्त नहीं, वाणिज्यिक कर विभाग ने जिला पंजीयकों को लिखा पत्र

रायपुर। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग संपत्ति के मूल्यांकन से होने वाले नुकसान को लेकर गंभीर हो गया है। इस संबंध में तमाम जिला पंजीयकों को पत्र लिखकर संपत्ति के न्यून मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाले राजस्व हानि रोकने के साथ प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में करने का निर्देश दिया गया है।

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा तमाम जिला पंजीयकों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित गाइडलाइन कीमतों से कम कीमत पर संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाए। यदि किसी प्रकरण विशेष में ऐसा प्रतीत होता है कि संपत्ति की कीमत गाइडलाइन दर से भी कम हो सकता है, तो नियमों के तहत साक्ष्यों के साथ प्रस्ताव भेजकर अनुमोदन के उपरांत आगे की कार्रवाई करने कहा गया है।

यही नहीं नई आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक परियोजना का मूल्य निर्धारण करते समय छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों को आधार बनाते हुए नियमों के अनुसार कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। साथ ही ताकीद किया गया है कि यादृच्छिक आधार पर दर अवधारित नहीं किए जाए।

पत्र में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष दर्ज प्रकरणों का निराकरण एक माह के भीतर सुनिश्चित करने कहा गया है। वहीं ऐसे प्रकरण में जहां जांच आवश्यक हो, कारण बताते हुए अधिकतम तीन माह के भीतर निराकरण करने कहा गया है।

यही नहीं जिला पंजीयकों के द्वारा निराकृत प्रकरणों की सूची 15 दिवस में एक बार, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। इन निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर गंभीर कदाचार मानते हुए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं : बैज

- पीसीसी चीफ ने भाजपा पर साधा निशाना,बोले- कब होगी पूर्ण शराबबंदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ बैज ने बीजेपी को पूर्ण शराबबंदी, फर्जी इनकाउंटर और आदिवासी मामले को लेकर घेरने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी मुद्दे को उठाने वाले अब इस मामले में मौन क्यों हैं। पीसीसी चीफ ने दावा करते हुए कहा कि चार जून को कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद देश के गरीब परिवार को राहत देने के लिए पांच किलो चावल की जगह 10 किलो चावल दिया जाएगा।

बैज ने आरोप लगते हुए कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद छत्तीसगढ़ में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्यों आदिवासियों को अभी तक सुरक्षित कर पाये पांच महिने में? उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हसदेव जंगल की कटाई हो रही है। कोरबा में बैगा परिवार की हत्या हो रही है। बस्तर में नक्सलियों के नाम से गोली मारा जा रहा है। निर्दोष बच्चों की विस्फोट में मौत हो रही है। इसके लिए सरकार क्या रही है? दीपक बैज ने मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल बताया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली से और उनकी प्रदेश में अभी तक समझ नहीं है। बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री

होने के बाद एक आदिवासी वर्ग को सुरक्षित नहीं कर पाये, इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं हो सकता।

पूर्ण शराबबंदी मामले को लेकर पीसीसी चीफ ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि राज्य सरकार बताए प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कब लागू होगी? उन्होंने मामले में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में शराब की कोचियागिरी शुरू हो गयी है। एसी अहाता बना कर शराब की खपत बढ़ाने के इंतजाम किये जा रहे है। दुकानों को कमीशन देकर कोचिये गली, मुहल्लों में शराब बेच रहे है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का पूरा प्रयास शराब की काली कमाई बढ़ाने में है।

पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि जहां गलत होगा कांग्रेस सवाल उठायेगी, कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। सवाल हम नहीं पीड़ित परिवार उठा रही है। उन्होंने कहा कि गांव वाले एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं कि कांकेर की घटना जहां तीन निर्दोष आदिवासियों को गोली मारा गया। क्या फर्जी एनकांउटर नही था? उसमें सरकार अभी तक क्यों जवाब नहीं दे रही है? उन्होंने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड सभी चीजे थी। गांव वालों ने कहा फर्जी एनकांउटर है, निश्चित तौर पर हम गांव वाले, आदिवासियों के साथ खड़े हैं। सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया। गांव वाले लगातार खुलकर बोल रहे है कि जो नक्सलियों बताकर मारे गये वो निर्दोष आदिवासी हैं। तेंदूपत्ता तोड़ने गये थे।

नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से कई ट्रेनें कैंसिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने मुंबई-हावड़ा से चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया है। मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के सीएसएमटी स्टेशन में प्लेटफार्म विस्तार का काम किया जा रहा है। इससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबन्धित कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है।

दरअसल, रेलवे प्रशासन की ओर से अधोसंरचना विकास के लिए मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के सीएसएमटी स्टेशन के प्लेटफार्म विस्तार के लिए स्टेशन और स्टेशन यार्ड में नॉन इंटरलाकिंग का काम किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है।

ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल- 31 मई को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12262 हावड़ा- सीएसएमटी दुरन्तो एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दो जून को सीएसएमटी से चलने वाली गाड़ी संख्या 12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरन्तो एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

गंतव्य से पहले खत्म होने वाली ट्रेनें- 16 मई से 31 मई तक हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12810 हावड़ा-सीएसएमटी सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी। 18 मई और 31 मई को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12870 हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी। 31 मई को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजली एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी। 31 मई और एक जून को गोंदिया से चलने वाली गाड़ी संख्या 12106 गोंदिया-सीएसएमटी एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी।

बेहद महत्वपूर्ण है चाबहार समझौता

अनिल त्रिगुणायत

भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के संचालन और प्रबंधन तथा परियोजना के आगामी चरण के विकास के लिए हुआ दीर्घकालिक समझौता एक महत्वपूर्ण परिघटना है। यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान के साथ खराब संबंध के कारण अफगानिस्तान और मध्य एशिया से हमारा संपर्क एक तरह से पूरी तरह कट गया है। कुछ समय पहले जब भारत 50 हजार टन अनाज मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान भेजना चाहता था, तब पाकिस्तान ने बहुत दिनों तक रास्ता देने में कोताही की थी, जबकि उसका दावा है कि वह अफगानिस्तान का दोस्त है। ऐसे में हमारे लिए एक वैकल्पिक मार्ग आवश्यक हो जाता है। भारत पहले से ही रूस और ईरान के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में चाबहार बंदरगाह की योजना बनी, जिस पर 2003 से काम चल रहा है। भारत ने उस बंदरगाह में शहीद बहिश्ती टर्मिनल को बनाया है और अनेक भारतीय कंपनियां संबंधित परियोजनाओं से जुड़ी हुई थीं। लेकिन काम अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा था क्योंकि ईरान पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगा दिये गये थे। हालांकि चाबहार बंदरगाह परियोजना तकनीकी रूप से प्रतिबंधों के दायरे में नहीं थी, लेकिन अनेक कंपनियों ने अमेरिकी पाबंदियों की आशंका से काम की गति को बहुत धीमा कर दिया था। इसी बीच पाकिस्तान ने चाबहार के नजदीक ही चीन के सहयोग से ग्वादर बंदरगाह बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। वह परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा योजना का हिस्सा है और उसमें सऊदी अरब का भी बहुत निवेश है। चाबहार में काम धीमा होने के बावजूद भारत और ईरान के बीच परियोजना के बारे में बातचीत होती रही थी। पहले हर साल समझौते का नवीनीकरण होता था तथा भारतीय कंपनी इंडिया ग्लोबल पोर्ट लिमिटेड शहीद बहिश्ती टर्मिनल को संभालती थी। लेकिन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। इस साल जनवरी में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान गये थे, तब इस मसले पर ईरानी राष्ट्रपति रईसी और संबंधित मंत्रियों से उनकी चर्चा हुई थी। उसी समय यह तय हुआ था कि ईरान पूरे चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन एवं संचालन का जिम्मा भारत को देगा। उस दौरे में भारत ने 120 मिलियन डॉलर के निवेश तथा 250 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण के लिए सहमति दी थी। दोनों देशों ने यह भी तय किया है कि यह बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का हिस्सा भी होगा। इस बंदरगाह के माध्यम से हमारे लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का सरल रास्ता मिल जायेगा। अब इसके लिए हमें पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं होगी। उन देशों को भी भारतीय बाजार और हिंद महासागर से जुड़ने का अवसर मिल सकेगा। यह बहुत अजीब बात है कि समझौते होने के साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग का एक बयान आ गया कि जो देश ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखेंगे, उन्हें भी प्रतिबंधों के दायरे में लाया जा सकता है। अमेरिका को यह अच्छी तरह से मालूम है कि अफगानिस्तान को मदद की दरकार है ताकि वह संकट और अस्थिरता से निजात पा सके। मध्य एशिया खुद अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह वहां पैठ बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अगर वह भारत के साथ मिलकर मध्य एशिया से अपने जुड़ाव को बेहतर करता, तो वह अच्छी बात होती। चाबहार परियोजना में यदि वे भारत के लिए अवरोध पैदा करते हैं, तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित ही कहा जायेगा। पहले उसने चाबहार परियोजना को पाबंदियों के दायरे से बाहर रखा था। उसे आगे भी ऐसा ही रवैया अपनाना चाहिए। अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह जिस डाल पर बैठा हो, उसे ही काटने लगे। जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है, अमेरिका भी मानता रहा है कि चाबहार परियोजना पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद है। इसी समझ के कारण इसे प्रतिबंधों से अलग रखा गया था। अमेरिका के हालिया बयान से यही संकेत मिलता है कि वह इस परियोजना पर भी पाबंदी लगाने के चक्कर में है। अपने भू-राजनीतिक एजेंडे के तहत अगर अमेरिका ऐसा करता है, तो इससे भारत को नुकसान तो होगा, उसको भी कोई लाभ नहीं होगा। अमेरिका चाहे जो कहे, भारत चाबहार बंदरगाह को लेकर गंभीर है। अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापक रणनीतिक समझौता है। इसके प्रावधानों और प्रक्रियाओं के तहत दोनों पक्षों में इस मसले पर बातचीत होगी। तब भारत उसके समक्ष इस परियोजना के बारे में समुचित जानकारी रखेगा और आशा है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक होगी। इस संबंध में भारत को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस को याद आया मुफ्त राशन

उमेश चतुर्वेदी

आम चुनावों के चार चरण बीत जाने के बाद इंडिया गठबंधन ने कुछ नए वायदे किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है मुफ्त राशन की सीमा को दोगुना करना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी को एक तरह से पीछे छोड़ने की कोशिश की है। लेकिन मुफ्त में दोगुना राशन देने के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वायदे ने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। सवाल यह है कि चार चरण बीतने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन को यह वायदा करना पड़ा। इस योजना पर अक्सर इंडिया गठबंधन के दल सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना भी लाजमी है कि क्या उन्होंने भी मान लिया है कि मुफ्त राशन योजना सही है और उसे ठीक से लागू किया जाना चाहिए।

वैश्विक महामारी कोरोना ने साल 2020 में जब पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया, तो पूरी दुनिया ही एक तरह से ठप हो गई थी। उस दौर में मोदी सरकार ने मुफ्त राशन की योजना शुरू की थी, जिसे महज एक साल के लिए ही लाया गया था। इसके तहत अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना शुरू हुआ। कोरोना पर काबू पाने के बाद जब जनजीवन पटरी पर आने लगा तो पहले इसे दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया और फिर राजनीतिक जरूरतों के लिहाज से इसे और पांच साल तक के लिए लागू कर दिया गया है।

मुफ्त राशन योजना लागू होने के बाद से हुए कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना इसके अपवाद रहे हैं। मोदी सरकार और बीजेपी को मुफ्त राशन योजना का चुनावी लाभ मिलता रहा है। मुफ्त राशन योजना की ही वजह से देश में एक नए शब्द का चलन बढ़ा है। मुफ्त राशन उठाने वाले लोगों को सियासी तौर पर लाभार्थी वर्ग कहा जा रहा है।

मुफ्त राशन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की वजह से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक बना है। इसी वजह से कांग्रेस समेत तमाम

मुफ्त राशन योजना लागू होने के बाद से हुए कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना इसके अपवाद रहे हैं। मोदी सरकार और बीजेपी को मुफ्त राशन योजना का चुनावी लाभ मिलता रहा है। मुफ्त राशन योजना की ही वजह से देश में एक नए शब्द का चलन बढ़ा है। मुफ्त राशन उठाने वाले लोगों को सियासी तौर पर लाभार्थी वर्ग कहा जा रहा है।

विपक्षी पार्टियां इस योजना का विरोध करती रही हैं। हालांकि मुखालफत का उनका तर्क कुछ अलग रहा है। मोदी सरकार दावा करती रही है कि उसके कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उपर लाया जा सका है।

भारत की आबादी करीब एक सौ चालीस करोड़ है। यानी देश की आबादी का पचपन फीसद से अधिक हिस्सा मुफ्त राशन के दायरे में आता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर विपक्षी दल बीजेपी और मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि अगर अस्सी करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंच रहा है तो आखिर कौन लोग हैं जो गरीबी रेखा से उपर लाए गए हैं।

विपक्षी दल मुफ्त अनाज योजना का विरोध करते हुए तर्क देते रहे हैं कि मुफ्त राशन देने के बजाय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुफ्त राशन योजना पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ की चर्चा भी विपक्ष करता रहा है। लेकिन ऐसे तर्क देने वाला विपक्ष जब आधे से ज्यादा चुनाव बीतने के बाद मुफ्त राशन की योजना के तहत दोगुना अनाज देने का वायदा करता है तो सवाल उठेंगे ही। तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि विपक्षी गठबंधन अपनी आशंकित हार के अंतर को कम करने के लिए यह नया वायदा लेकर आया है?

मौजूदा चुनाव प्रक्रिया के बीच सोशल मीडिया पर विपक्षी खेमा कहीं ज्यादा सक्रिय और ताकतवर नजर आ रहा है। 2014 और 2019 की तुलना में बीजेपी की अगुआई वाला सत्ताधारी खेमा सोशल मीडिया पर विपक्षी हरावल दस्तों की तुलना में कमजोर नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर बीजेपी खेमे की उपस्थिति का सबसे बड़ा हिस्सा उस वर्ग का है, जो वैचारिक रूप से बीजेपी और संघ परिवार का समर्थक है। उसे निजी तौर पर बीजेपी से कोई लाभ हासिल नहीं हो रहा है। जबकि विपक्षी खेमे की ओर से सोशल मीडिया पर सक्रिय दस्तों में से ज्यादातर को विपक्षी खेमे से आर्थिक और दूसरे तरह के फायदे मिलने की खबर है।

अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो लगेगा कि मौजूदा चुनावों में बीजेपी की अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि लाभार्थी वर्ग, जातीय गणित और नरेंद्र मोदी की महिला, अति पिछड़े समेत कुछ वर्गों के बीच स्थापित क्रेज की वजह से जमीनी स्तर पर चुनाव का दृश्य सोशल मीडिया की तुलना में कुछ और है। चार चरणों में हुई वोटिंग में एक और प्रवृत्ति दिखी है। बीजेपी और मोदी सरकार से कुछ वजहों से चिढ़े हुए पारंपरिक वोटर, मतदान केंद्रों पर जाकर बीजेपी या उसके गठबंधन वाले दलों को ही वोट दे रहे हैं। वैसे आम बहसों और विमर्श में वे बीजेपी के कटु आलोचक हैं। बीजेपी को वोट देने को लेकर उनका तर्क है कि तुलनात्मक रूप से यही पार्टी ठीक है। इसका एक मतलब यह हुआ कि बीजेपी के बरक्स खड़े विपक्षी खेमे की साख मोदी और बीजेपी के आलोचकों के एक बड़े वर्ग में भी नहीं है।

चुनाव को लेकर अपना अनुभव यह है कि उसकी असलियत राजनेता और राजनीतिक दल बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा गहराई से समझते हैं। बशर्ते कि वह चापलूस पसंद ना हो और उसके इर्द-गिर्द चापलूस नेता ना हों। वह असल सूचनाओं और चापलूसी वाली जानकारियों में फर्क कर सकता हो। शायद विपक्षी खेमे को अंदाजा लग गया है कि चुनाव की जमीनी हकीकत कुछ और है। इसीलिए उसने अपना नुकसान कम करने के लिए मुफ्त राशन योजना को बढ़ाकर दोगुना करने का वायदा किया है। इस योजना की घोषणा करते वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चूंकि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसा कर चुकी है, लिहाजा उसी तर्ज पर यह योजना पूरे देश में लागू की जाएगी।

कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने एक साल और तेलंगाना में करीब छह माह हो चुके हैं। अगर कांग्रेस को अपनी इस योजना पर इतना ही भरोसा था तो उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे क्यों नहीं शामिल किया। न्याय पत्र में पार्टी अपनी इस योजना को क्यों भूल गई? अगर उसे अपनी यह योजना इतनी ही बेहतर लगती थी तो वह इसे चार चरणों के चुनाव के बाद लेकर क्यों आई। अगर इन सवालों के जवाब खोजे जाएंगे तो उनका सीधा उत्तर तो यही नजर आता है कि चार चरणों के चुनाव के बाद विपक्षी खेमे और कांग्रेस को मतदाताओं की नजर में अपनी जमीनी हकीकत पता चल चुकी है, इसी वजह से वह नए वायदों की पोटली खोल रही है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामणि उपनिषद् (भाग-5)

गतांक से आगे...

यह गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राणविद्या है-महाविद्या है, जो कुण्डलिनी से उद्भूत है। इस प्रकार जो जान लेता है, वही वेदवेत्ता है। कुण्डलिनी शक्ति कन्द के ऊर्ध्वभाग में आठ कुण्डलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुँह को अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है। जिस मनोमय ब्रह्म द्वार (सुषुम्ना) में प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार (मुख) को अपने मुख से ढककर यह परमेश्वरी शक्ति (कुण्डलिनी) सोई रहती है।

वह्नियोग (अग्नियोग) के द्वारा जाग्रत् होकर यह प्रकाश के रूप में मन और प्राणवायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। कुंजी के द्वारा जिस तरह से घर का किवाड़ (ताला) खोलते हैं, उसी प्रकार कुण्डलिनी के द्वारा योगी लोग मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं।

दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगाकर हाथों को ऊपर-नीचे गोदी में रखकर सम्पुटित करे, पुनः सिर नीचा करके ठोड़ी को छाती से लगाये, इसके बाद ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करके, बार-बार श्वास को भीतर खींचे और बाहर निकाले।

प्राणवायु अन्दर ले जाए और अपान वायु ऊपर ले जाए। इस तरह प्राणायाम करने से मनुष्य को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास के श्रम से जो पसीना निकलता है, उसे शरीर में ही मसल लेना चाहिए तथा नमकीन, खट्टे, कड़वे पदार्थों का परित्याग करना चाहिए और दूध एवं दूध से बने भोजन का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए।

ब्रह्मचारी और मिताहार वाला योगी यदि योग के अभ्यास में लग जाए, तो एक वर्ष में ही योग की सिद्धि प्राप्त कर लेगा, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए।

क्रमशः ...

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस

नुपुर

संग्रहालय इतिहास के खजाने की तरह होते हैं जहां पर संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली अवशेषों और कलाकृतियों को सुरक्षित रखा जाता है। यह अमूल्य धरोहर न केवल हमें अपनी विरासत से जोड़ते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसे में संग्रहालय की महत्ता को समझाने के लिए हर साल 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है।

हर साल दुनियाभर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर के संग्रहालयों और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे की स्थापना 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय

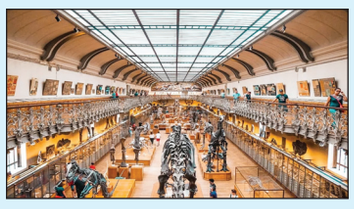

परिषद द्वारा की गई थी। तब से लेकर हर साल यह दिवस मनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2009 में 90 से ज्यादा देशों के 20,000 संग्रहालयों ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस में हिस्सा लिया, 2010 में 98 देश, 2011 में 100 देश और 2012 में 129 देशों के करीब 30,000 इस महत्वपूर्ण दिवस में हिस्सा लिया था। अब हर साल 150 देशों से विभिन्न संग्रहालय और सांस्कृतिक संगठन इसमें भाग ले रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाये जाने पर विचार पहली बार साल 1951 में, मास्को, रूस में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित एक बैठक में सामने आया। यह एक महत्वपूर्ण पहल थी जिसका उद्देश्य था दुनियाभर में संग्रहालयों के महत्व और योगदान को मान्यता देना। ऐसे में 18 मई 1977 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। तब से लेकर हर साल ये दिवस मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर विश्व के कई देशों के अंदर स्थापित संग्रहालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और संग्रहालय के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाते हैं।

विश्व के कई देशों में स्थापित संग्रहालय (म्यूजियम) हमें कलाकृतियों, वस्तुओं और अवशेषों के माध्यम से अतीत की कहानियां सुनाते हैं और वर्तमान को समझने में हमारी मदद करते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और प्राकृतिक दुनिया को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी कड़ी में दुनियाभर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिवस संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संग्रहालयों के पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ाने और संग्रहालयों की सराहना करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस में दुनियाभर के संग्रहालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। कई संग्रहालय अपने प्रदर्शनियों में लोगों के लिए मुफ्त प्रवेश प्रदान करते हैं, ताकि लोगों को कलाकृतियों और ऐतिहासिक वस्तुओं को करीब से देखने का मौका मिल सके, स्कूल और कॉलेज के छात्रों को संग्रहालयों में ले जाया जाता है ताकि उन्हें सांस्कृतिक विरासत में महत्व के बारे में सिखाया जा सके।

पाकिस्तान में दुबई 'अनलॉक्ड बम' से तहलका

मरिआना बाबर

भारतीय मीडिया के पत्रकार इन दिनों देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं। उनके पास या तो समय नहीं है या पाकिस्तानी मीडिया में फूटे बम में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। दुबई अनलॉक्ड शीर्षक से छपी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में उन लोगों के नाम उजागर किए गए हैं, जिन्होंने दुबई में संपत्तियां खरीदीं। कम से कम पाकिस्तान में दुबई अनलॉक्ड प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में सुर्खियों में है और आने वाले हफ्तों में इस पर बहस होगी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसे समय में जब मुल्क आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से दूसरे बेलआउट पैकेज के लिए गुहार लगा रहा है, पाकिस्तानियों ने विदेश में 11 अरब डॉलर की संपत्ति खरीदी है। हालांकि दुबई अनलॉक्ड को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि भारतीय करोड़पतियों ने दुबई में निवेश के मामले में पाकिस्तानियों को पछाड़ दिया है। 29,700 भारतीय नागरिकों ने 17 अरब डॉलर की 35,000 संपत्तियां दुबई में खरीदी हैं।

वैसे यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के बाहर संपत्ति खरीदना अवैध नहीं है। कई लोगों ने विदेशों में संपत्ति खरीदी है या कर चुकाई गई आय का उपयोग संपत्ति खरीदने में किया है। संपत्ति की वैधता तय करना संबंधित देश के कर अधिकारियों पर निर्भर है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई मामलों में सैन्य और असैन्य अभिजात वर्ग ने अपने आयकर रिटर्न में दुबई की इन संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया है, खासकर राजनेता, जिनके आयकर रिटर्न सार्वजनिक हैं।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में नागरिकों के बीच भारी असमानता है, जहां उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण हजारों पाकिस्तानियों के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर

पाकिस्तानी समाज के हर तबके में यह अभिजात वर्ग है, जिसने इतनी संपत्ति जमा कर ली है कि उनके पास दुबई में महल तक हैं।

पाकिस्तान की पिछली सरकारों ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों से इकामा (प्रवास वीजा) हासिल करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या और वहां किए गए निवेशों के नाम और विवरण पाने की कोशिश की थी, लेकिन यूएई अधिकारी इन विवरणों को साझा करने में अनिच्छुक रहे हैं। एक दर्जन से अधिक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों एवं उनके परिजनों सहित बैंकरों एवं नौकरशाहों ने दुबई के महंगे इलाकों में संपत्तियां खरीदी हैं। इनमें जनरल परवेज मुशर्रफ और कई अन्य जनरल शामिल हैं। राजनेताओं में पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ (पीटीआई) नेता इमरान खान की बहनें, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का परिवार और यहां तक कि मौजूदा गृहमंत्री मोहसिन नकवी और इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त शामिल हैं। जैसा कि एक टिप्पणी में कहा गया है कि एक विकासशील देश, जो आर्थिक पतन के कगार पर है, अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं और मित्र देशों से भीख मांग रहा है, वहां के नागरिकों का विदेशों में इतनी भारी मात्रा में निवेश आश्चर्यजनक है।

इसके अलावा, पाकिस्तान में इन दिनों?मुल्क की ताकतवर सेना और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव की चर्चा है। पिछले नौ महीने से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पीटीआई नेता इमरान खान ने हाल ही में कोर्ट में एक पेशी के दौरान संदेश दिया कि वह सैन्य नेताओं से बात करना चाहते हैं। लेकिन उनके संदेश का खंडन किया गया और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक ने चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने एक मीडिया सम्मेलन में कहा कि अगर इमरान खान बात करना चाहते हैं, तो उन्हें राजनीतिक दलों से संपर्क करना चाहिए, न कि सेना से।

अब इमरान खान जिद पर अड़े हुए हैं और कहते हैं कि वह सेना प्रमुख को पत्र लिखेंगे, लेकिन पत्र का मजमून क्या होगा, इसका खुलासा नहीं करते। वह मुख्य राजनीतिक दलों, जिनमें से कई सरकार में शामिल हैं, से बात करने से इन्कार करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वे %शक्तिहीन% हैं और असली ताकत रावलपिंडी में है। हालांकि सैन्य जनरल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अभी जेल में रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने संकेत दिया है कि उन्हें राहत मिलेगी और यहां तक कि उन्हें सभी मामलों में जमानत देकर जेल से बाहर रहने की इजाजत दी जाएगी।

फिलहाल एक बड़े घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अदियाला जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से अपने मामले की पैरवी करने पर मंजूरी दी है। हाल में सभी अदालती मामलों का सुप्रीम कोर्ट से सीधा प्रसारण किया जा रहा है और इससे आम पाकिस्तानी को पहली बार देश की शीर्ष अदालत से लाइव कार्यवाही देखने का मौका मिला है।

पिछले नौ महीनों से इमरान खान की कोई भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए कोई नहीं जानता कि वह बदल गए हैं या नहीं। हालांकि उनके वकीलों, पार्टी नेताओं और परिवार को उनसे मिलने की अनुमति है, लेकिन फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। यदि मामला अगले सप्ताह टेलीविजन पर लाइव दिखाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट सेना के अलिखित आदेशों की अवहेलना करेगी, जिसने जनता को उनकी कोई भी छवि देखने से मना किया है। इस बीच बिना नेतृत्व के इमरान खान के समर्थकों की रुचि भी घटती जा रही है और हाल ही में जब जुलूस और रैलियां निकालने का आह्वान किया गया, तो उपस्थिति नगण्य थी। पीटीआई के भीतर की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है और सरकार की सख्ती के कारण कई पीटीआई कार्यकर्ता जेल में हैं और कुछ पर सैन्य मुकदमा चल रहा है, जिससे पार्टी सबसे कमजोर नजर आ रही है।

इस बीच राजनेताओं द्वारा एक गोलमेज सम्मेलन कर मुल्क की अर्थव्यवस्था तथा लगातार आतंकवादी हमलों से संबंधित तात्कालिक चुनौतियों पर चर्चा करने की कोशिश की जा रही है। इस सम्मेलन में कई लोग पीटीआई को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां राजनीतिक मतभेदों से परे मुल्क की स्थिरता के लिए एक न्यूनतम सहमति वाला कार्यक्रम तैयार किया जा सके। कई लोग सेना को भी आगाह कर रहे हैं कि उसे पीटीआई के प्रति भी उदार रुख अपनाना होगा और हाल के चुनावों में एक मजबूत वोट बैंक के साथ मजबूत होकर उभरने के बाद उसे जगह देनी होगी। उसे जनादेश से वंचित करने से केवल गतिरोध ही पैदा होगा।

आज का इतिहास

1940 जर्मनी की सेना ने ब्रूसेल्स पर कब्जा किया।
1944 मोंटे कैसिनो की लड़ाई 18 मई, 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस बलों द्वारा इटली में विंटर लाइन के खिलाफ मित्र राष्ट्रों द्वारा चार हमले की 123 दिनों की श्रृंखला के बाद समाप्त हुई थी।
1944 लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिस्लाव एंडर्स के तहत द्वितीय विश्व युद्ध-पोलिश बलों ने चार महीने के अंतराल के बाद, मोंटे कैसिनो, इटली पर कब्जा कर लिया।
1944 सोवियत संघ ने जबरन तातार की पूरी आबादी को उज्बेक एसएसआर और अन्य जगहों पर विशेष बसेरा के रूप में निर्वासित कर दिया।
1950 अमेरिका और यूरोप की रक्षा के लिए 12 नाटो सदस्य देशों ने स्थाई संगठन बनाने पर सहमति जताई।
1953 अमेरिकी जैकलीन कोचरन 18 मई, 1953 को सुपरसोनिक जाने वाली पहली महिला पायलट बनीं जब उन्होंने कनाडायर एफ -86 सेबर जेट विमान उड़ाया और ध्वनि अवरोधक को तोड़ दिया।
1953 रोजर्स ड्राई लेक, कैलिफोर्निया में, उनके कैनाडेयर सेबर में, अमेरिकनजैकी कोचरन ध्वनि अवरोध को तोड़ने वाली पहली महिला पायलट बनीं।
1955 स्वतंत्रता के लिए ऑपरेशन पास, 310,000 वियतनामी नागरिकों, सैनिकों और फ्रांसीसी-वियतनामी सदस्यों के साम्यवादी उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम के लिए प्रथम इंडोचाइना युद्ध की समाप्ति के बाद निकासी समाप्त हो गई।
1956 ल्होत्से का मुख्य शिखर पहली बार 18 मई, 1956 को अर्न्स्ट रीस और फ्रिट्ज़ लुचिंगर की एक स्विस टीम द्वारा चढ़ा गया था। यह दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है जो 8,516 मीटर की दूरी पर है और तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है।
1965 एली कोहेन, एक जासूस, जिसे सीरिया के खिलाफ छह-दिवसीय युद्ध में इजरायल के असफल होने का श्रेय दिया जाता है, चार महीने पहले सार्वजनिक रूप से पकड़े जाने के बाद सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी।
1991 ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री हेलेन शर्मन ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। 27 वर्षीय हेलेन सोवियत सोयुज़ नाम की अंतरिक्ष कैपसुल में बैठकर कज़ाख़स्तान से रवाना हुई।
2004 इस्त्रायल के राफा विस्थापित कैम्प में इस्त्रायली सैनिकों ने 19 फिलीस्तीनियों को मौत के घाट उतारा।

डर दिखा कर चुनाव जीतने की रणनीति से किसे लाभ?

अजय सेतिया

जब चुनाव शुरू हुआ था, तब राहुल गांधी जाति आधारित आरक्षण के अपने एजेंडे पर चल रहे थे। भले ही उन्हें नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के जाति आधारित जनगणना नहीं करवाने के निर्णयों से जुड़े तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन पहले चरण की वोटिंग तक राहुल अपने एजेंडे से टस से मस नहीं हुए थे। राहुल गांधी को लगता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को प्रभावित कर रहा है। बल्कि उसमें बाद में उन्होंने देश के हर नागरिक की सम्पत्ति का सर्वेक्षण करवाने का मुद्दा भी जोड़ दिया था। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद ही जब भाजपा इन दोनों मुद्दों पर हमलावर हुई तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने पर लोकतंत्र खत्म होने और संविधान बदलने का डर दिखाना शुरू कर दिया।

जब पहले चरण की वोटिंग कम हुई थी, जिसका अर्थ यह निकल रहा था कि भाजपा को पहले चरण की वोटिंग में कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, तब होना तो यह चाहिए था कि विपक्ष अपने एजेंडे को और जोरदार ढंग से उठाता। वह कह सकता था कि हम सत्ता में आएंगे तो सुप्रीमकोर्ट से लड़ कर हर किसी को उसकी आबादी के अनुपात में शिक्षा और नौकरी का आरक्षण दिलाएंगे। लेकिन विपक्ष ने मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के नतीजों का डर दिखाना शुरू कर दिया कि मोदी इसलिए 400 सीटें मांग रहे हैं क्योंकि वह आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जहां तक लोकतंत्र के खत्म होने और आख़िरी चुनाव होने का डर दिखाने की बयानबाजी थी, उसका समाज के किसी वर्ग पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, इसलिए नरेंद्र मोदी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संविधान बदल कर उसमें से सेक्यूलर शब्द हटाने का डर भी समाज में कोई असर नहीं डाल रहा था, इसलिए नरेंद्र मोदी उस पर भी नहीं बोले।

लेकिन जब संविधान से आरक्षण हटाने की बात की जाने लगी, तो मोदी और शाह को लगा कि विपक्ष का यह प्रचार भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अतीत में आरएसएस और भाजपा के कुछ लोगों की ओर से भी जाति आधारित आरक्षण खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत होती रही थी। संघ और भाजपा नेताओं के पुराने बयान दलितों, आदिवासियों और ओबीसी में भ्रम पैदा करने में कारगर साबित हो सकते थे, इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संविधान और आरक्षण पर अपना स्टैंड क्लीयर किया। मोदी ने कहा कि वह तो क्या डॉक्टर आम्बेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण कम करने या खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता मोदी और शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर यह कह कर उलटे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया कि अगर वह सत्ता में आ गई तो दलितों और आदिवासियों के कोटे से धर्म परिवर्तन करके मुसलमान और ईसाई बनने वालों को आरक्षण दे देगी। साथ ही उसी तरह देश के सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके हिन्दुओं को मिलने वाले आरक्षण का हक मार लेगी।

विपक्ष ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को आरक्षण खत्म करने का डर दिखा कर मोदी और शाह को बचाव मुद्रा में ला दिया था, लेकिन अरविन्द केजरीवाल ने अपने भीतर का डर जाहिर करके इंडी एलायंस के लिए सेल्फ गोल कर लिया। जो बात उन्होंने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस में कही थी, उसे लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कांफ्रेंस में भी दोहरा दिया कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों के अंदर ही योगी आदित्यानाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। इसका

मतलब यह हुआ कि वह जनता को डर दिखा रहे हैं कि जिस योगी आदित्यनाथ ने यूपी से माफिया राज और गुंडागर्दी खत्म की, जनता के उस प्रिय मुख्यमंत्री को मोदी हटा देंगे। इस का मतलब यह भी है कि अखिलेश यादव के साथ बैठ कर उन्होंने योगी आदित्यनाथ का समर्थन और तारीफ़ की है।

दूसरी बात केजरीवाल ने यह कही कि मोदी 75 साल की आयु पूरी होते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी अमित शाह को दे देंगे। तो अपने इस बयान से भी वह जनता को डराना चाह रहे हैं कि मोदी वोट तो अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन वह अमित शाह को पीएम बना देंगे। इसका अर्थ यह निकलता है कि जनता में मोदी की अपील का असर है और उनकी अपील पर भाजपा तीसरी बार जीतने जा रही है।

इसका तीसरा अर्थ यह निकलता है कि उन्हें मोदी से ज्यादा अमित शाह से डर है कि जिस तरह पहली बार गृहमंत्री बनते ही उन्होंने 370 को निपटाया था, उसी तरह दूसरी बार गृहमंत्री बनते ही दिल्ली विधानसभा पर ही तलवार न चला दें, जो पिछले 25 साल से भाजपा के गले की हड्डी बनी हुई है। पहले 1998 से 2013 तक कांग्रेस जीतती रही और 2013 से आम आदमी पार्टी जीत रही है। मोदी और शाह ने बचाव में ही सही दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को डर दिखाया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो उनके आरक्षण का कोटा वह मुसलमानों को दे देगी। यह बात इन तीनों वर्गों के गले उतरनी स्वाभाविक है। इसके साथ ही चुनाव हिन्दू-मुस्लिम ध्रुवीकरण के पुराने एजेंडे पर लौट आया है।

नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषणों में खुलेआम हिन्दुओं को विपक्ष के मुस्लिम एजेंडे का डर दिखाया जाने लगा है। चौथे चरण तक उत्तर प्रदेश की सिर्फ 26 और पश्चिम बंगाल की सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश की 54 और बंगाल की 26 सीटों पर चुनाव बाकी है। चौथे चरण की वोटिंग आते आते हिन्दू मुस्लिम ध्रुवीकरण तेज हो गया, जो इन दोनों ही राज्यों में बहुत मायने रखता है।

पांचवें चरण की वोटिंग से पहले दो बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात तो यह हुई है कि बीच चुनाव में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन क़ानून को लागू करके पाकिस्तान से आए कुछ हिन्दुओं को नागरिकता के प्रमाण पत्र बांट दिए। इससे भाजपा ने बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसे हिन्दुओं को संदेश दे दिया है कि केंद्र में मोदी सरकार बनते ही उन्हें भी नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ममता बनर्जी ताल ठोक कर कह रही हैं कि जब तक नागरिकता संशोधन क़ानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाता, वह मौजूदा नागरिकता संशोधन क़ानून लागू नहीं होने देगीं। जबकि अमित शाह ताल ठोक कर कह रहे हैं कि संसद के बनाए क़ानून को कोई राज्य सरकार नहीं रोक सकती।

दूसरी बात यह हुई है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू करते ही मथुरा और ज्ञानवापी का मुद्दा उठा दिया है। हालांकि अब तक मथुरा और काशी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर नहीं थे, लेकिन हेमंत बिस्व सरमा ने उन दोनों मन्दिरों को भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बता कर उत्तर प्रदेश के यादव और ब्राह्मण वोट बैंक को साफ़ संदेश दिया है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद सरकार इन दोनों मन्दिरों को मुक्त करवाने का काम शुरू करेगी। भले ही हल्के से लेकिन अमित शाह ने भी मथुरा और काशी का मुद्दा उठाया है।

इसके अलावा पांचवें दौर की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस.जयशंकर और हेमंत बिस्व सरमा ने एक साथ पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का राग अलापना शुरू कर दिया है। यह एक ऐसा मौक़ा है जब पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगभग उसी तरह की बगावत शुरू हो चुकी है, जैसे 1970 में मौजूदा बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी और शेख मुजीबुर रहमान की रहनुमाई में मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था। जब पूर्वी पाकिस्तान के नागरिक सीमा पार करके भारत में घुस रहे थे, इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय फ़ौज ने हमला करके पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया था।

अब उसी तरह के हालात पाक अधिकृत कश्मीर में बन रहे हैं, और वहां आज़ादी के नारे लगने शुरू हो गए हैं। कश्मीर सभी भारतीयों लेकिन खासकर उत्तर भारतीयों के लिए भावनात्मक मुद्दा है, जिसे मोदी सरकार ने जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। इस पर फारूख अब्दुल्ला का यह बयान ईंडी एलायंस के गले की हड्डी बन गया है कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखीं। उनका यह बयान पाकिस्तान की पैरवी करने वाला है।

कुछ नेताओं का सब कुछ दांव पर है इन चुनावों में

राजकुमार सिंह

बेशक 18 वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव केंद्रीय सत्ता का फैसला करेंगे, लेकिन कुछ नेताओं का इनमें सब कुछ दांव पर लगा है। हार के बावजूद उनका वजूद तो शायद बचा रहे लेकिन चुनावी राजनीति में प्रासंगिकता शायद ही बचे। बात बहुजन समाज पार्टी से शुरू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चमत्कारिक रफ्तार से बढ़ी बसपा अपने बूते भी सत्ता तक पहुंची। मायावती ने देश के सबसे बड़े राज्य का चार बार मुख्यमंत्री बनने का करिश्मा कर दिखाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन में 19.3 प्रतिशत वोट की बदौलत 10 सीटें जीतने में सफल बसपा अकेले लड़ने पर 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.88 प्रतिशत वोट और मात्र एक सीट पर सिमट गई। जो दस सांसद जीते थे, उनमें से भी ज्यादातर इस चुनाव से पहले हाथी का साथ छोड़ गए। लोकसभा चुनाव बसपा अकेले लड़ रही है। इस चुनाव में बसपा चमत्कार नहीं कर पाई तो राजनीतिक शोध का विषय बन कर रह जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल का भी सब कुछ इस चुनाव में दांव पर है। कांग्रेस से अलग भारतीय क्रांति दल बनानेवाले चौधरी चरण सिंह बाद में प्रधानमंत्री भी बने। हार-जीत होती रही, दल का नाम भी बदलता रहा, पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से भी आगे पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा तक फैले उनके जनाधार और क्षत्रपों पर सवालिया निशान नहीं लगा। उनके निधन के बाद, खासकर मंडल-कमंडल के राजनीतिक ध्रुवीकरण के चलते वह जनाधार उनके बेटे अजित सिंह के जीवनकाल में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सिमट गया। अजित के बेटे जयंत चौधरी में चरण सिंह की छवि देखनेवालों को उम्मीदें बहुत थीं, पर उन्होंने जिस तरह विपक्ष से पलटी मार कर मात्र दो लोकसभा सीटों के लिए सत्तापक्ष का दामन थाम लिया, उसके नतीजे किसान राजनीति के सबसे बड़े चौधरी की विरासत का भविष्य भी तय कर देंगे। वैसी ही चुनौती बिहार में चिराग पासवान के समक्ष है। रामविलास पासवान, लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाली लोकदली-समाजवादी राजनीतिक धारा से निकले। नीतीश की राजनीति लंबी नहीं बची है। लालू के वारिस के रूप में तेजस्वी ने खुद को स्थापित कर लिया है, लेकिन मायावती के अलावा उत्तर भारत में दूसरे बड़े दलित चेहरे के रूप में उभरे पासवान की विरासत पर संकट है। पहले लोक जनशक्ति पार्टी, भाई और भतीजे के बीच बंट गई तो अब चुनावी परीक्षा है। चुनाव केंद्र की सत्ता के लिए है, पर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी परिणामों का गहरा असर होगा। एकनाथ शिंदे की असली परीक्षा इन चुनावों में है। यही हाल अजित पवार का है।

रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह ने जोरदार तरीके से ताल ठोक रखी है

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश का रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र वीआईपी इलाके माने जाते हैं क्योंकि यह दशकों से गांधी परिवार के गढ़ के रूप में विख्यात हैं। आप जब किसी वीआईपी क्षेत्र या गढ़ की कल्पना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में ऐसी छवि उभरती है कि वहां विकास की गंगा बह रही होगी और सबकुछ सर्वोत्तम होगा। चूंकि यह क्षेत्र दशकों से गांधी परिवार का गढ़ रहा है तो आपको लगेगा कि उन्होंने यहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी होगी। लेकिन जब आप इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो पाएंगे कि जनता ने तो खूब प्यार और सम्मान दिया लेकिन गांधी परिवार ने इस क्षेत्र के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। खासतौर पर रायबरेली तो अब तक गांधी परिवार के साथ रहा था लेकिन यहां की टूटी सड़कें और विकास का अभाव क्षेत्र के साथ सांसद की बेरुखी को दर्शाता है। जब मीडिया की टीम रायबरेली पहुँची तो लोगों ने हमसे शिकायत की कि पहले तो कभी कभार सोनिया गांधी क्षेत्र में आ भी जाया करती थीं लेकिन 2019 में जीतने के बाद उन्होंने पूरी तरह मुंह फेर लिया। लोगों ने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई उस समय तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्र की जनता की मदद करते दिखे लेकिन सोनिया गांधी ने रायबरेली की कोई सुध नहीं ली। लोगों ने कहा कि यहां तक सोनिया गांधी के लिए वोट मांगने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी मुसीबत के वक्त लोगों का हालचाल जानने नहीं आईं। लोगों ने कहा कि हमने यहां से चुनाव जिता कर भेजा लेकिन सोनिया गांधी जीत का प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आईं। लोगों ने कहा कि हम हमेशा यही सुनते रहे कि सोनिया गांधी अस्वस्थता के कारण यहां नहीं आ पा रही हैं लेकिन जब अपने लड़के राहुल गांधी का नामांकन भरवाना था तब वह यहां आ गयीं। लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में राहुल गांधी से ज्यादा प्रयंका गांधी आती हैं इसलिए यदि सोनिया को अपने बच्चों में से ही किसी को टिकट देना था तो प्रियंका को उतारा जाना चाहिए था।

मीडिया से बातचीत में लोगों ने कहा कि पिछले पांच साल में जनता अपने सांसद को ढूंढ़ती रह गयी लेकिन वह नहीं मिलीं

इसलिए इस बार हम इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। जब हमने पूछा कि कौन-सा इतिहास दोहराने की तैयारी है तो लोगों ने कहा कि जैसे राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए रायबरेली की जनता ने चुनाव हरवाया था उसी प्रकार इस बार उनके पोते को हार मिलेगी। लोगों ने कहा कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं वह अक्सर विदेश दौरों पर रहते हैं इसलिए जीत के बाद उन्हें यहां आने का मौका नहीं मिलेगा। जनता ने यह भी कहा कि हम यह भी जानते हैं कि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों सीटों से यदि वह जीत गये तो वायनाड को ही बरकरार रखेंगे क्योंकि उन्हें एक वर्ग को खुश रखना है। लोगों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि राहुल गांधी यहां से जीतें और फिर हमें अपने काम करवाने के लिए अपने सांसद को ढूँढ़ना पड़े। लोगों ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह हमारे बीच के हैं और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। जनता से उनका हमेशा संपर्क रहता है और हमें ऐसा ही नेता चाहिए।

हम आपको बता दें कि रायबरेली में विधायक अदिति सिंह को उम्मीद थी कि उन्हें कांग्रेस का साथ छोड़ कर भाजपा में आने का प्रतिफल मिलेगा और संसदीय चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया जायेगा। इसी प्रकार हाल ही में राज्यसभा चुनाव में सपा विधायक दल के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडेय ने भी इस उम्मीद में पाला बदला था कि उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा लेकिन उम्मीदवार बना दिये गये योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। इसके चलते यह दोनों नेता नाराज बताये जा रहे थे लेकिन भाजपा ने अब इनको मना लिया है। रायबरेली के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा विधायक अदिति सिंह को मनाया जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब सब ठीक है और यह चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। वहीं मनोज पांडेय को मनाने के लिए अमित शाह उनके घर ही पहुँच गये। माना जा रहा है कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव हरवाने के लिए भाजपा सारे राजनीतिक समीकरण साध चुकी है।

राहुल गांधी भले इस क्षेत्र में नाई की दुकान पर जाकर इस क्षेत्र से अपना लगाव दर्शा रहे हों, अपनी दो मां- दादी और मम्मी के इस क्षेत्र से जुड़ाव की लोगों को याद दिला रहे हों, भले उनकी बहन यहां डेरा जमा कर बैठ गयी हों और घर-घर जाकर प्रचार कर रही हों लेकिन इस क्षेत्र में आकर यह साफ पता लगता है कि पिछले पांच साल में गांधी परिवार ने जिस तरह रायबरेली की उपेक्षा की उसके चलते लोगों का उस परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव कम या खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद जमीनी स्थिति का पता है इसीलिए उन्होंने हाल ही में एक साक्षात्कार में दावा कर दिया कि राहुल गांधी की रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी हार होगी। इसके अलावा हमने यहां के दौरे पर पाया कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्षेत्र के लोगों को मिला है और अपने जीवन में आये इस बदलाव के लिए वह मोदी के मुरीद नजर आये। साथ ही रायबरेली में लगभग हर घर पर लगा जयश्रीराम का झंडा दर्शा रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र के लोग कितने खुश हैं।

रायबरेली संसदीय क्षेत्र के चुनावी इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि 1996 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अशोक सिंह ने पहली बार कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई थी। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के अशोक सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में ही थे। वह जानते हैं कि कांग्रेस अपनी चुनावी बिसात इस सीट पर कैसे बिछाती रही है इसलिए उनको अपना काम आसान नजर आ रहा है। देखना होगा कि यहां चुनाव का परिणाम क्या रहता है लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी रायबरेली को जितना आसान समझ कर यहां आये हैं यह सीट उतनी आसान उनके लिए है नहीं।

मोदी के इकोसिस्टम पर राहुल का इकोसिस्टम पड़ रहा भारी

संजय तिवारी

राहुल गांधी जब से राजनीति के मैदान में लाये गये हैं तब से उन्होंने कांग्रेस के इतिहास में संभवतः पहली बार विचारधारा की राजनीति की बात करना शुरु कर दिया। जो कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं कहा गया उसे राहुल गांधी ने यूं ही नहीं कहना शुरु किया। विचारधारा की राजनीति हमेशा संगठन के सहारे की जाती है। जबकि कांग्रेस की राजनीतिक बनावट ऐसी है कि उसके पास सांगठनिक ढांचा बचा नहीं है और विचारधारा वाली राजनीति तो उसने कभी की ही नहीं। फिर भी राहुल गांधी ने अगर ये कहना शुरु किया कि वो एक विचारधारा से लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको किसी न किसी समूह द्वारा यह बात समझायी गयी है।

अब सवाल यह है कि राहुल गांधी किस विचारधारा से लड़ रहे हैं और खुद उनकी विचारधारा क्या है? राहुल गांधी घोषित तौर पर आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल यह है कि देश के भीतर वह कौन है जो आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहा है और क्यों? तो इस सवाल का जवाब है, कम्युनिस्ट पार्टियां और वो आरएसएस की विचारधारा से इसलिए लड़ती आ रही हैं क्योंकि आरएसएस उनके वर्ग संघर्ष वाले सिद्धांत और मुस्लिम सांप्रदायिकता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए लंबे समय से कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी, पत्रकार, षड्यंत्रकार, साहित्यकार सब मिलकर आरएसएस को एक शैतानी सोच वाला संगठन साबित करने का प्रयास करते आ रहे हैं। आरएसएस का हिन्दू राष्ट्र भी कम्युनिस्टों को बिल्कुल हजम नहीं होता और न ही अखण्ड भारत का सिद्धांत वो पचा पाते हैं। जब तक कांग्रेस में कद्दावर नेता रहे, वे कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों को अपने आसपास पालते जरूर रहे लेकिन उनके विचार को कभी कांग्रेस पर हावी नहीं होने दिया। लेकिन जिस दिन से राहुल गांधी कांग्रेस का भविष्य बने पूरा कम्युनिस्ट इकोसिस्टम राहुल गांधी के इर्द गिर्द जमा हो गया। बंगाल में सीपीएम के पतन के बाद विश्वविद्यालयों से निकले छात्रनेता हों या लंबे समय से कांग्रेस की छत्रछाया में पल रहे कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी। उन्हें राहुल गांधी में एक ऐसा ब्लैंक स्पेस नजर आया जहां अपनी विभाजनकारी योजनाओं को भर सकते थे और

उनके जरिए पूरे देश में उसका प्रचार भी कर सकते थे। लगभग एक दशक से कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी ऐसा कर भी रहे हैं। राहुल और प्रियंका के आसपास कम्युनिस्टों का यही घेरा उनका अपना वो इकोसिस्टम है जिसके प्रभाव में वो विचारधारा की राजनीति की बात बड़बड़ाते रहते हैं। इस इकोसिस्टम में सैम पित्रोदा, रघुराज रामन जैसे लोग भी हैं जो अपने इन्नोवेटिव आइडियाज से कांग्रेस को फायदा कम, नुकसान अधिक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मोटे तौर पर कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों का जमावड़ा ही कांग्रेस का इकोसिस्टम बन गया है जो यह तय करता है कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे या फिर कांग्रेस कहां किस बात पर क्या स्टैंड लेगी। नरेन्द्र मोदी की दस साल की सरकार में बार बार ऐसे बेवजह के मुद्दे उठाये गये जो राजनीतिक मांग से अधिक कम्युनिस्टों की विचारधारा से प्रभावित थे। राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो असफल कोशिश कर चुके हैं, वह कुछ और नहीं बल्कि भारत में %हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों% के बचाव में शुरु किया गया अभियान था जो बुरी तरह पिट गया। फिर भी कांग्रेस की विचारधारा निर्धारित करनेवाला यह इकोसिस्टम ऐसे धूर्त और षड्यंत्रकारी लोगों का समूह है जो कोई भी नया प्रपंच रचने और उसे देश भर में चर्चा का विषय बना देने में सक्षम है।

इसके विकल्प में जो भाजपा का इकोसिस्टम है वह बौद्धिक रूप से कमजोर और प्रतिक्रियावादी है। दो दशक पहले तक पार्टियों की राजनीति पत्रकारों के भरोसे ही चला करती थी। यह तब की बात है जब टीवी चौबीस घण्टे का नहीं हुआ था या फिर सोशल मीडिया की शुरुआत नहीं हुई थी। कांग्रेस या फिर दूसरे दलों की तरह भाजपा के पास भी अपने समर्थक पत्रकारों की टोली थी जो पार्टी की पहुंच को बढाने में मदद किया करती थी। लेकिन सोशल मीडिया के उदय के बाद और खासकर नरेन्द्र मोदी के उभार के बाद भाजपा का एक इकोसिस्टम तो बना है। सोशल मीडिया और मीडिया को छोड़ दें तो बाकी जगह जो लोग मोदी के समर्थन में खड़े दिखाई भी देते हैं तो वो भाजपा से अधिक मोदी से प्रभावित लोग हैं। इसमें भी मैन्युफैक्चर्ड सपोर्टर्स का रोल बीते दो चुनावों में रहा है जिसका लाभ भी मोदी को मिला है। लेकिन इस बार के चुनाव में उसका अभाव दिख रहा है। मोदी या फिर कहें भाजपा का कोई ईकोसिस्टम है तो वह टीवी और सोशल मीडिया तक सिमटा हुआ है। बीते दस सालों से भाजपा ने जो नैरेटिव वार लड़ा है उसका आधार यही लोग रहे हैं।

खासकर सोशल मीडिया में राष्ट्रवादी समर्थक जो पैदा हुए वो भले ही सीधे तौर पर भाजपा या आरएसएस से जुड़े हुए न हों लेकिन उनके बोलने से कहीं न कहीं भाजपा को फायदा तो हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया के ये नेशनलिस्ट उस तरह से भाजपा के इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाये हैं जैसे कांग्रेस समर्थक कम्युनिस्ट या लिबरल पत्रकार बन गये हैं। वो एक एजंडा सेट करते हैं और सामूहिक रूप से उसका माहौल बनाते हैं। जबकि भाजपा या मोदी समर्थक इकोसिस्टम सिर्फ प्रतिक्रियावादी है। वह उन मुद्दों की हवा तो निकाल सकता है लेकिन खुद उनके खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर सकता। फिर भाजपा समर्थित इस इकोसिस्टम की अपनी बहुत सीमित सोच है। अधिकतर ये लोग हिन्दू मुसलमान के बंटवारे में ही उलझे रहते हैं जबकि कांग्रेस इकोसिस्टम से जुड़े लोग धर्म, जाति, संप्रदाय, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, नफरत, खान-पान और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे विविध मुद्दों पर जब चाहते हैं, मोदी और भाजपा को घेरते रहते हैं।

अगर दोनों ही धड़ों के इकोसिस्टम का आकलन करें तो बौद्धिक रूप से कांग्रेस समर्थक धड़ा ज्यादा ताकतवर है। जबकि मोदी समर्थक इकोसिस्टम इस चुनाव में एन्टी मुस्लिम माहौल बनाने से आगे नहीं निकल पाया है। इस बार चुनाव में एन्टी मुस्लिम माहौल बनता है या नहीं बनता है, यह तो चार जून का चुनाव परिणाम बतायेगा लेकिन दस साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी समर्थक इकोसिस्टम उस कांग्रेस के इकोसिस्टम के सामने बहुत कमजोर ही नजर आ रहा है जो दस साल से सत्ता से बाहर है।

आर्थिक रूप से पिछड़ों को मिले संसद में आरक्षण?

संदीप अग्रवाल

जाति धर्म से अलग हटकर मोदी सरकार ने पहली बार आर्थिक रूप से गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस प्रकार से संसद में धनबल वालों का प्रभाव बढता जा रहा है, क्या उससे निपटने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को संसद में आरक्षण दिया जाना चाहिए? लोकतंत्र में देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उसे सार्थक बनाता है। लेकिन, जिस तरह से बीते कुछ सालों में संसद में अमीर सांसदों की संख्या बढ़ी है, वह इस बात को दर्शाती है कि यहाँ देश की बहुसंख्य गरीब आबादी का प्रतिनिधत्व लगातार सिकुड़ रहा है। बीते चार चरणों में कुल 5,879 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। एसोसिएयशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच के आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1708 प्रत्याशी करोड़पति या इससे अधिक सम्पन्न हैं। इन करोड़पतियों में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं जिनके पास 4 करोड़ का बैंक बैलेन्स है। करीब डेढ़ अरब आबादी वाले देश में, एक करोड़ या इससे अधिक आय जाहिर करने वाले करोड़पतियों की संख्या 2.16 लाख है। जबकि लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या 475 है। यानि सांसदों की कुल संख्या का 88%। वर्ष 2004 में निर्वाचित लोकसभा में कुल 28% अर्थात 156 सांसद ही करोड़पति थे। यह स्थिति शायद इसलिए आई है कि आज राजनीति का पूर्ण पूंजीकरण हो चुका है। चुनावों में टिकट पाने से लेकर चुनाव प्रचार तक की पूरी प्रक्रिया बेहद खर्चीली हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के अध्ययन बताते हैं कि एक करोड़ से कम सम्पत्ति वाले प्रत्याशियों के जीतने की संभावना महज एक फीसदी ही थी और करोड़पति उम्मीदवारों की 21 फीसदी। यह आकलन कितना सही था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले करीब 2400 करोड़पति उम्मीदवारों में से लगभग बीस फीसदी विजयी रहे और बाकी 5600 गैर-करोड़पति उम्मीदवारों में करीब सवा फीसदी। इस बार चुनावों पर करीब एक लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है, जो पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में दो गुना और 2014 के लोकसभा चुनाव खर्च का करीब पच्चीस गुना है। पहली लोकसभा के लिए हुए चुनावों में कुल 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से हम इस बार करीब दस हजार गुना ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। जितने खर्च में पहली लोकसभा के सारे चुनाव निपट गए थे, उसका करीब अस्सी फीसदी खर्च इस बार एक उम्मीदवार पर आ रहा है। इतनी बड़ी रकम हम इसलिए खर्च करते हैं कि देश की जनता को उनकी बात कहने के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि मिल सकें। लेकिन, जब नतीजे आते हैं तो प्रतिनिधित्व का पूरा अनुपात एकदम विपरीत होता है। हम अक्सर अमीरी और गरीबी के बीच की बढ़ती हुई खाई को लेकर चिंताएं व्यक्त करते हैं, लेकिन जब यही स्थिति सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्थान में भी दिखाई देने लगे तो चिंताएं और गहरा जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अमीरों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। हमारा संविधान उन्हें भी चुनाव लड़ने का उतना ही अधिकार प्रदान करता है, जितना किसी अन्य व्यक्ति को। लेकिन, दिक्कत यह है कि ऐसे में जबकि राजनीतिक दलों को विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को प्रोत्साहित और समर्थन करना चाहिए, जीत की एक प्रतिशत और इक्कीस प्रतिशत संभावनाओं में से उनके लिए भी मजबूरी हो जाती है कि वे सम्पन्न उम्मीदवारों को ही तरजीह दें। संसद में धनबल के बढ़ते दबदबे के बीच ऐसे उपाय खोजे जाने चाहिए जो सभी वर्गों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए एक पहल यह हो सकती है कि जिस तरह से समाज के दूसरे कई वर्गों के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनावों में सीटें आरक्षित की गई हैं, उसी तरह से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी सीटें आरक्षित करने पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। हो सकता है कि इसमें कुछ साल लग जाएं, लेकिन महिला आरक्षण की तरह इसे भी एक हकीकत का रूप दिया जाना असंभव नहीं है।

आलू से निखारें चेहरे का ग्लो

आलू फेस मास्क में मौजूद विटामिन सी आपकी त्वचा को ब्राइटन करने में मदद करेंगे। इसके लिए आधा आलू को कद्दूकस करके उसमें 1 टेबल स्पून बेसन और 1 टीस्पून नींबू का रस मिलाएं। इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अंत में, पानी की मदद से चेहरे को धो दें। स्किन में निखार पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। घर पर मौजूद नेचुरल इंग्रीडिएंट्स की मदद से स्किन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। मसलन, अगर आप अपनी स्किन की डार्कनेस को दूर करके पार्लर जैसा ग्लो पाना चाहती हैं तो ऐसे में आलू का इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू को स्किन लाइटनिंग एजेंट के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण यह आपकी स्किन को ब्राइटन करने में मददगार है। आप इसे एक नहीं, बल्कि कई अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको इस बारे में बता रहे हैं-

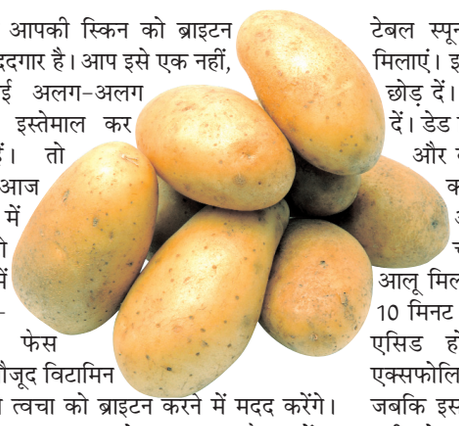

आलू फेस मास्क में मौजूद विटामिन सी आपकी त्वचा को ब्राइटन करने में मदद करेंगे। इसके लिए आधा आलू को कद्दूकस करके उसमें 1 टेबल स्पून बेसन और 1 टीस्पून नींबू का रस मिलाएं। इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अंत में, पानी की मदद से चेहरे को धो दें। डेड स्किन सेल्स को हटाकर इवन स्किन टोन और ब्राइटन स्किन बनाने के लिए आप आलू का स्क्रब भी बना सकती हैं। इसके लिए आधा छोटा चम्मच ओटमील और आधा चम्मच दूध में आधा कद्दूकस किया हुआ आलू मिलाएं। इस मिश्रण से अपने चेहरे को 8 से 10 मिनट तक धीरे से स्क्रब करें। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो इस फेस स्क्रब के एक्सफोलिएटिंग प्रभाव को भी मजबूत करेगा जबकि इसमें मौजूद फैटी एसिड आपकी त्वचा में नमी को बनाए रखने में मदद करेगा। डार्क सर्कल आपकी नेचुरल ब्यूटी को छीन लेते हैं और आपको थका हुआ दिखा सकते हैं। ऐसे में आलू की मदद से अपनी इस समस्या को अलविदा कहें। आलू के दो स्लाइस पर एलोवेरा लगाएं। अब इन्हें अपनी आंख पर रखकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। अंत में, इन्हें हटाएं और चेहरे को धो लें। एक तरफ आलू आपके काले घेरों को हल्का करेगा और दूसरी तरफ एलोवेरा सूजन को शांत करेगा। फ्रेश लुक के लिए हर दूसरे दिन इस उपाय को आजमाएं।

जानें इस्तेमाल का तरीका

आपके बाल पतले होते जा रहे हैं तो अपनाएँ घरेलू नुस्खे

सुन्दर और घने बाल महिलाओं का ताज माने जाते हैं / लम्बे और घने बालों की हसरत सभी को होती है लेकिन हर किसी के बाल मोटे और घने नहीं होते / कई बार देखा गया है की जिनके बाल पहले घने होते थे लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही बाल भी पतले और कमजोर होने शुरू हो जाते हैं /ऐसे में सबाल यह उठता है की बाल आखिर पतले और बेजान क्यों होते जा रहे / बालों की सही देखभाल ना करना , तनाब , गलत खानपान ,शरीर में पौषक तत्वों की कमी और हार्मोनल असंतुलन बालों के झड़ने और पतले होने का मुख्य कारण माना जाता है लेकिन अगर आप इस समय कुछ उपाय अपनाते हैं तो आपकी समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

पतले और बेजान बालों के लिए आंबला जूस और निम्बू का रश काफी सहायक होता है / रोजाना नहाने से आधा घण्टा पहले अपने बालों में आंबला और नीम्बू का रश लगाएं / इससे आपके बाल मोटे और घने होंगे / हफ्ते में तीन बार प्याज का रस लगाने से भी बालों में चमक आएगी और बाल कोमल और मुलायम होंगे

सेब के सिरके का प्रयोग करें

क्षतिग्रस्त बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको इस उपाय को जरूर आजमाना चाहिए। इससे बालों के झड़ने की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर , 1 चम्मच शुद्ध बादाम का तेल लें / सबसे पहले एक छोटी कटोरी में सिरका और तेल मिलाएं फिर बालों में लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। बालों को शॉवर कैप लगाएं और इसे कम से कम एक घण्टे के लिए छोड़ दें। निर्धारित समय के बाद अपने बालों को हलके शैम्पू से धो लें। इस नुस्खे से आपको कुछ ही दिनों में अपने बालों में फर्क दिखने लगेगा।

नारियल के दूध की मदद लें

नारियल के दूध में मौजूद फैटी एसिड आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करता है। यह आपके बालों के झड़ने की समस्या को कम करने में भी मदद करता है और उनके स्वास्थ्य पर काम करता है।1 कप नारियल का दूध और 1/ 4 कप करी पत्ते का पाउडर लें / सबसे पहले करी पत्ते का पाउडर बना लें या फिर आप बाहर से पाउडर खरीद सकते हैं। एक कटोरे में दूध और पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें और बालों में लगा लें। इसे बालों पर लगाएं और कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर अपने बालों को हमेशा की तरह धो लें।

तिल के तेल का प्रयोग करें

सफेदए, रूखे , रूसी, बालों का झड़ना और पतले बालों के लिए तिल के तेल से बेहतर और क्या हो सकता है। यह बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में भी मदद करता है। 1/ 2 कप तिल का तेल को गर्म कर लें /इसमें एक कॉटन बॉल डूबा कर इसे अपनी खोपड़ी पर लगाएं तथा खोपड़ी की हलके हाथों से मसाज करें इसे लगाकर रात भर छोड़ दें और सुबह नींबू के टुकड़ों को स्कैल्प पर मलें। 30 मिनट के बाद अपने बालों को हलके शैम्पू से धो लें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी परेशानी कम हो जाएगी।

नारियल तेल और करी पत्ते का प्रयोग कर

करी पत्ते में ऐसे तत्व होते हैं जो जड़ों पर अच्छे से काम करते हैं और बालों के विकास में मदद करते हैं। यह प्रोटीन, बीटा कैरोटीन और ऐसे कई एंटीऑक्सिडेंट का स्रोत है जो बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बालों के तंतुओं पर कार्य करते हैं। एक पैन में 1/ 2 कप नारियल का तेल और 6-7 करी पत्ता डालकर गरम करें। इसे तब तक उबालें जब तक आपको पैन में काला पदार्थ दिखाई न दे। ठंडा करके मिला लें। फिर सिर पर अच्छी तरह लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें तथा बाद में बालों को साफ ताजे पानी से धो डालें / अगर आप इस नुस्खे को हफ्ते में 2 से 3 बार आजमाएंगे तो आपको जल्द ही फर्क नजर आने लगेगा।

शादी पर दिखना है सबसे हैंडसम दूल्हा तो शेरवानी खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें

आने वाले महीने से शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में यहां हम दूल्हों के लिए कुछ शॉपिंग टिप्स लेकर आएं हैं जो शेरवानी खरीदने में उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आपकी शादी जल्द होने वाली है और आपने शॉपिंग शुरू कर दी तो ये बातें आपके काम आ सकती हैं। शादी वाले दिन सबसे ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए यहां देखें कैसे खरीदें सही शेरवानी।

फिटिंग पर दें ध्यान- शेरवानी खरीदते समय उसकी फिटिंग पर ध्यान दें। वैसे तो इसे खरीदते समय आपके बॉडी साइज लिया जाता है, लेकिन आपको हमेशा इसकी फाइनल फिटिंग चेक करनी चाहिए। स्टाइलिश दिखने के लिए शेरवानी की सही फिटिंग जरूरी है। अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आप फिटिंग चार्ट को चेक करे। सब कुछ सही नाप का हो तो ही खरीदें।

फैब्रिक पर दें ध्यान- शादी वाले दिन शेरवानी को घंटों तक पहनना होता है, इसलिए इसके कपड़े की क्वालिटी पर ध्यान दें। लोग अकसर शेरवानी को हैवी कपड़े में खरीदते हैं। हालांकि आपको इसे मौसम के मुताबिक खरीदना चाहिए। आप जब भी शेरवानी खरीदें उसे पहनकर जरूर देखें। कपड़ा आरामदायक हो तभी उसे खरीदें।

साफा और जूती पर दें ध्यान- शेरवानी के साथ मैचिंग जूती और साफा आपके लुक को काफी हद तक इंहेंस कर देता है। हैवी शेरवानी के साथ प्लेन साफा और जूती काफी अच्छा लगेगा। वहीं प्लेन शेरवानी के साथ आप कुछ हैवी साफ देख सकते सकते हैं।

एक्सेसरीज भी हैं जरूरी- दूल्हे के लुक को इंहेंस करने के लिए जूलरी भी जरूरी होती है। ऐसे में आप शेरवानी से मैच करती जूलरी खरीद सकते हैं। हालांकि इन दिनों कॉन्ट्रास्ट जूलरी भी काफी ट्रेंड में हैं।

स्टोल पर दें ध्यान- शेरवानी भले ही हल्की हो या हैवी, लेकिन उसके साथ स्टोल जरूरी है। ये आपके स्टाइल को रॉयल लुक देता है।

माधुरी दीक्षित के इन लुक्स को करें रिक्रिएट

करवाचौथ किसी भी सुहागन स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा त्योहार होता है। अगर आपने भी इस बार सबसे अलग व खूबसूरत दिखने की तैयारी कर ली है तो पहले एक बार माधुरी दीक्षित के इन लुक्स को जरूर देखें। माधुरी दीक्षित के यह लुक्स किसी भी उम्र की महिला बेहद आसानी से रिक्रिएट कर सकती है।

यकीन मानिए, इसके बाद आपके पति की नजरें सिर्फ और सिर्फ आप पर ही टिकी रहेंगी- महिलाएं रेड कलर पहनना काफी पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप एक सिंपल और एलीगेंट तरीके से रेड कलर कैरी करना चाहती हैं तो माधुरी दीक्षित की तरह मल्टीकलर लहंगा पहना जा सकता है। इस लुक में माधुरी ने हाई नेक फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ मैचिंग लहंगा और चुनरी कैरी की है। आप भी इस लहंगे के साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स, झूमके या चांदबाली पहनकर अपने लुक को एन्हॉन्स कर सकती हैं। माधुरी दीक्षित का यह रेड साड़ी लुक भी काफी अलग है आपके लुक में एक्सफैक्टर एड कर सकता है। आप भी माधुरी दीक्षित की तरह रेड पोल्का डॉट साड़ी पहन सकती हैं। माधुरी ने इस लुक में बैलून स्लीव्स क्रीमी कलर के ब्लाउज को पेयर किया है। लेकिन आप फेस्टिवल लुक के लिए सीक्वेंस ब्लाउज को भी पहन सकती हैं। इवनिंग लुक को ध्यान में रखते हुए मेकअप को बोल्ड टच दिया जा सकता है। फेस्टिवल सीजन में रेड के अलावा महिलाएं ग्रीन और येलो कलर पहनना भी काफी पसंद करती हैं। ऐसे में आप माधुरी दीक्षित के इस येलो कलर लहंगे को आसानी से रिक्रिएट कर सकती हैं।

उन्होंने इस लुक में येलो कलर के फ्लोरल लहंगे को पहना है, जिसमें ब्लाउज पर हैवी वर्क किया गया है और इसलिए करवाचौथ के दिन आप दोपहर के समय इस लहंगे को पहन सकती हैं। तो आपको माधुरी दीक्षित का कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा और आप किस लुक को रिक्रिएट करना पसंद करेंगी? यह हमें फेसबुक पेज के कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा।

आईलैशेज कर्लर का इस्तेमाल करते समय इन बेसिक बातों का रखें ध्यान

कर्ल की हुई आइलैशेज किसे पसंद नहीं है? हर लड़की चाहती है कि उसकी आंखें पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आए। इसके लिए आईलाइनर अप्लाई करने के अलावा आईलैशेज को हाइलाइट करने के लिए गर्ल्स आई कर्लिंग का भी इस्तेमाल करती हैं। ट्विस्टेड लैशेज आपकी आंखों की खूबसूरती को ही हाईलाइट नहीं करती बल्कि इससे आपकी ओवरऑल खूबसूरती भी ज्यादा निखरकर सामने आती है।

आइए, जानते हैं आपको आईलैश कर्लर का यूज करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर किसी की पलकें अलग होती हैं, एक व्यक्ति के लिए काम करने वाला कर्लर आपके लिए काम नहीं कर सकता है। यह समझना जरूरी है कि आपकी पलकों को क्या चाहिए, इसलिए कर्लर चुनते समय अपनी आंखों के आकार और लैश की लंबाई को ध्यान में रखें। अपने आईलैश कर्लर को अपनी मेकअप किट में रखने से पहले इसे धोकर साफ कर लें। मेकअप रिमूवर वाइप्स भी आपके आईलैश कर्लर से मस्कारा हटाने का एक बेहतरीन तरीका है। पूरी तरह से सफाई करके इसे सुखाकर ही रखें।

हमेशा अपनी पलकों को पहले कर्ल करें, फिर मस्कारा लगाएं। इससे उल्टा दोहराने से लैश कर्लर गंदा हो सकता है, जिससे आपकी पलकें टूट सकती हैं क्योंकि मस्कारा उन्हें सख्त कर देता है। लोग अक्सर अपने आईलैश कर्लर को अपनी पलकों पर दबाना और धीरे-धीरे कर्लर को ऊपर उठाना भूल जाते हैं, लेकिन यह एक जरूरी स्टेप कदम है जिसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यह आपकी लैशेज को कुछ कर्ल और एक इंस्टेंट लैश लिफ्ट देगा, साथ ही उनके कर्ल को लंबे समय तक बनाए रखेगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

विभव के साथ 'बेशर्मी' से घूम रहे हैं केजरीवाल : सीतारमण

नईदिल्ली। राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से कथित बदसलूकी का मामला गरमाता जा रहा है। जहां शुक्रवार को बीजपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाद प्रदर्शन किया। वहीं मामले को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर करारा प्रहार किया है। सीतारमण ने कहा कि यह अविश्वसनीय एवं अस्वीकार्य है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा कार्रवाई का वादा किए जाने के बाद केजरीवाल आरोपी विभव कुमार के साथ 'बेशर्मी से' घूम रहे हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मांग करती हूं कि वह मालीवाल के मुद्दे पर बोलें और माफी मांगें। उन्होंने कहा कि 'आप' सांसद स्वाति मालीवाल पर दबाव था और यह अब भी बना हुआ है।

विभव कुमार राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष नहीं हुए पेश

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित बदसलूकी के सिलसिले में शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। एनसीडब्ल्यू ने कुमार को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा था। एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग की एक टीम बृहस्पतिवार को कुमार को नोटिस देने उनके आवास पर गई थी, लेकिन वह घर पर नहीं थे। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, कुमार की पत्नी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। मेरी टीम शुक्रवार को फिर पुलिस के साथ उनके आवास पर गई और अगर वह शनिवार तक (एनसीडब्ल्यू के समक्ष) पेश नहीं होते हैं, तो हम पूछताछ करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाएंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि सोमवार सुबह मालीवाल यहां सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंचीं और आरोप लगाया कि केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उन पर हमला किया।

टीएमसी ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में तामलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दरअसल, भाजपा उम्मीदवार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीएमसी कानूनी कार्रवाई का भी सहारा लेगी। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करके शिष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी। गुरुवार को जारी एक वीडियो में जस्टिस गंगोपाध्याय को यह कहते हुए सुना गया कि ममता बनर्जी को कितनी कीमत पर बेचा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे पर संजय राउत का तंज

मुंबई। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में पीएम मोदी जितनी रैली करेंगे, भाजपा उतनी ही कम सीट जीतेगी। हमारी रैलियां न हो, इसलिए हमें शिवाजी पार्क नहीं मिला। राज ठाकरे पहले उनके खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि मोदी-शाह को महाराष्ट्र में पैर रखने नहीं देंगे, लेकिन आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। संजय राउत ने आगे कहा, राज्य में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ माहौल है। भाजपा को यहां सबसे बड़ा नुकसान होगा। गौतम अदाणी को जमीन बेचने के लिए कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। भाजपा का सबसे बड़ा फायनेंसर अदाणी ही है। महाराष्ट्र में भाजपा के गठबंधन का दम निकल चुका है। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने बताया कि उन्होंने रैली के लिए शिवाजी पार्क की तैयारी की थी। उन्होंने कहा, हमने सभी कागजी कार्रवाई भी की थी।

हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन शोधन घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। दरअसल, सोरेन ने हाल ही में कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खुद के लिए जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में अब अगली तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट अब सोरेन की जमानत याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेगा। इससे पहले अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देनी वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 17 मई तक जवाब मांगा था। 13 मई को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू में मामले की सुनवाई 20 मई को सूचीबद्ध की थी लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा और अगर मामले में लंबी तारीख दी गई तो वह (सोरेन) पक्षपात का शिकार होंगे।

नई बुआ की शरण में समाजवादी पार्टी के शहजादे, बाराबंकी में बोले प्रधानमंत्री मोदी-

सपा-कांग्रेस तुष्टिकरण के आगे घुटने टेक चुकी है

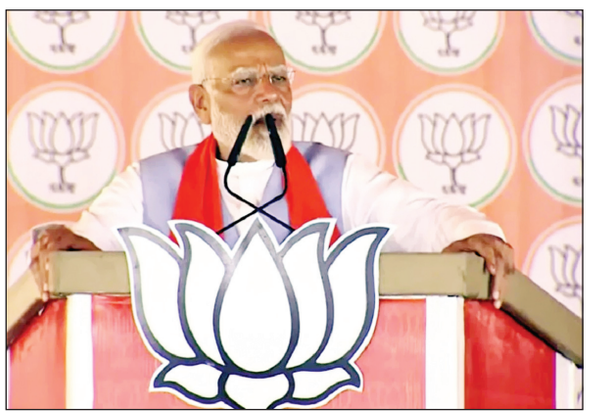

लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 की प्रचार प्रक्रिया के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (17 मई) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4 जून बहुत दूर नहीं है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। नई सरकार में मुझे गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं। इसलिए मैं बाराबंकी और मोहनलालगंज के लोगों से आशीर्वाद मांगने आया हूं।

मोदी ने कहा कि आज एक तरफ देशहित के लिए समर्पित भाजपा-एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तो की तरह बिखरने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यहां जो बबुआ यानी समाजवादी शहजादे हैं, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। उनकी ये नई बुआ बंगाल में है। अब उनकी बंगाल वाली बुआ ने इंडी गठबंधन वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है कि खबरदार अगर हमारे खिलाफ पंजाब में बोला। पीएम पद को लेकर भी ये सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके सपनों की इंतहा देखिए, कांग्रेस के एक नेता ने कहा दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया, बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमान बह गए। उन्होंने कहा कि आपको काम करने वाले और आपका भला करने वाले सांसद चाहिए। 5 साल मोदी को गाली देने वाले नहीं, क्षेत्र का विकास करने वाले सांसद चाहिए। इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है - कमल। उन्होंने कहा कि 100 सीसी के इंजन से आप 1,000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार ही दे सकती है... भाजपा सरकार ही दे सकती है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां सपा के बड़े नेता ने रामनवमी के दिन कहा कि राम मंदिर तो बेकार है। वहीं, कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। इनके लिए सिर्फ अपना परिवार और पावर ही मायने रखते हैं। सपा-कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए, तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इंडी गठबंधन के सहयोगियों पर तीखा कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लेना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की भलाई के लिए काम कर रहा है, जबकि दूसरी ओर इंडी गुट गड़बड़ी पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा, जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, इंडी गठबंधन के सदस्य टूटने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए लोकसभा चुनाव मैदान में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि सपा-कांग्रेस के लिए अपने वोटबैंक से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन, जब मैं इनकी पोल खोलता हूं, तो ये बैचेन हो जाते हैं, इनकी नींद हराम हो जाती है। ये कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि केंद्र में सरकार आई तो सभी की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा और आपके लॉकर में जो कि सोना-चांदी और धन है उसे लेकर वोट जेहाद करने वालों को दे दिया जाएगा। सपा-कांग्रेस हिंदू-मुसलमान की राजनीति करते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले संविधान का अपमान करते हैं। डॉ. आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध करते थे पर कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को तुष्टिकरण की प्रयोगशाला बनाया हुआ है।

मोदी ने कहा कि बिहार के इनके चारा घोटाले के चैंपियन, जो अभी जेल से तबियत के बहाने बाहर घूम रहे हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़ों के पास कुछ बनेगा ही नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा-कांग्रेस तुष्टिकरण के आगे घुटने टेक चुकी है। और मोदी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है...तो ये कहते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस वोटबैंक के पीछे ये लोग भागते हैं, वो भी अब इनकी सच्चाई समझने लगे हैं। तीन तलाक कानून से खुश हमारी माताएं-बहनें भाजपा को लगातार आशीर्वाद दे रही है।

'पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट'

लोकसभा चुनाव के तहत देश में चार चरण के लिए मतदान हो चुके हैं, अब तीन चरण के लिए वोटिंग होनी है। इसको लेकर रैलियों का दौर जारी है। इस क्रम में शुक्रवार को पीएम मोदी ने यूपी के फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इज़्ज़त बचाने के लिए अब 'मिशन 50' रखा है। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह पचास का आंकड़ा मिल जाएग। इसके लिए अब वे इधर उधर हाथ पैर मारते नजर आ रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस इंडी गठबंधन का टायर पहले दिन से पंचर हो वो कितनी आगे जाएगी, एक न एक दिन उसका भट्ठा बैठना ही था और वो बैठ गया। फतेहपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठीकरा किस्से फोड़ा जाए, खटाखट खटाखट। उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है, खटाखट खटाखट।

रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक अपील, बोलीं-

मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, राहुल निराश नहीं करेंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त रैली की। एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे परिवार की जड़ें इस धरती की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। गंगा मां की तरह पवित्र इस रिश्ते की शुरुआत अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन से हुई। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए विशेष स्थान था। मैंने उन्हें बहुत करीब से काम करते देखा है।

सोनिया ने कहा कि मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी है, जो इंदिरा जी और रायबरेली की जनता ने मुझे दी थी; सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो। अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, जिससे भी लड़ना पड़े, लड़ जाओ। डरना मत.. क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि आपके प्यार ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका है... मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। आपको उसे स्वीकार करना होगा, जैसे आपने मुझे स्वीकार किया। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि 20 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे ही अमेठी भी मेरा घर है। यहां से न केवल मेरे जीवन की कोमल यादें जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 10 साल से देश की जनता प्रताड़ित हो रही है, न्याय के लिए पुकार रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, गरीबों की एक पुकार न सुनी। अब देश की पुकार है कि नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंका जाए। रायबरेली की जनता पूरे देश को ये संदेश दे कि हम एक स्वच्छ राजनीति चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि रायबरेली में उमड़ा ये जनसैलाब इस बात की बानगी है कि राहुल गांधी जी रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हर जगह से अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। मोदी जी भी देख लें - राहुल गांधी जी का रायबरेली से सच्चा रिश्ता है। रायबरेली में एक और एक ग्यारह हो गया है और भाजपा नौ दो ग्यारह हो गई है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो चाहूं.. नरेंद्र मोदी से बुलवा सकता हूं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही.. 4 जुलाई को लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए पहुंच जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे।

मैं अमेठी का था, हूं और रहूंगा : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल यही चाहते हैं कि कुछ लोग अमीर बने रहें और बाकी लोग गरीब रहें। उन्होंने कहा कि जब मैं सिर्फ 12 साल का था, तब पहली बार अपने पिता के साथ अमेठी आया था। मैंने अपनी आंखों से अपने पिता और अमेठी के बीच मोहब्बत भरा रिश्ता देखा है। मेरी भी ऐसी ही राजनीति है। मैं अमेठी का था.. अमेठी का हूं और अमेठी का रहूंगा।

खेल
प्रमुख समाचार

आरसीबी से हारकर भी सीएसके प्लेऑफ में कर सकती है क्वालीफाई

नईदिल्ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शनिवार, 18 मई को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2024 का अपना आखिरी मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेगी। यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि विजेता के आईपीएल 2024 प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करने की संभावना है। आरसीबी और सीएसके में से कोई एक ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकता है। एसआरएच और जीटी के बीच वॉशआउट ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम ने शीर्ष 4 में जगह बना ली है। सीएसके या आरसीबी में से एक ही प्लेऑफ में केकेआर, आरआर और एसआरएच के साथ शामिल होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के के 13 मैच में 14 अंक हैं। अगर सीएककके 18 मई को आरसीबी के खिलाफ जीत जाती है तो वह प्लेऑफ के लिए बिना किसी समस्या के क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन अगर सीएसके हार जाती है तो क्या होगा। आरसीबी से हारने पर भी सीएसके प्लेऑफ के लिए कैसे क्वालीफाई कर सकती है? हम इन्हीं समीकरणों की तहकीकात करने जा रहे हैं। आरसीबी को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए सीएसके पर एक अच्छी जीत की जरूरत है। टीम फिलहाल 12 अंकों और +0.387 के रन रेट के साथ अंक तालिका में छठे स्थान पर है। दूसरी ओर, सीएसके के 14 अंक हैं और नेट रन रेट +0.528 है। आरसीबी को 14 अंक तक पहुंचने और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए सीएसके के खिलाफ जीत की जरूरत है। इसके बाद क्वालीफायर का फैसला नेट रन रेट से होगा। आरसीबी पहले खेलते हुए सीएसके को 18 रनों से हराए। या 18.1 ओवर में लक्ष्य का पीछा करे। सीएसके को रन रेट (200 के पहली पारी के स्कोर को मानते हुए) से पीछे करने के लिए ये जरूरी है। इसी तरह यदि सीएसके यह सुनिश्चित कर सकती है कि वे 17 रनों से अधिक के अंतर से या 18.2 ओवर से पहले न हारें, तो वे आरसीबी के रन रेट से आगे रहेंगे और प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई कर लेगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 253 अंक चढ़ा निफ्टी 22,400 के पार

नईदिल्ली। एक दिन पहले काफी उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनियों में खरीदारी से बढ़त के साथ बंद हुए। व्यापक बाजारों ने बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों के साथ बेंचमार्क इंडेक्स को पीछे छोड़ दिया। यह एक फीसदी से ज्यादा की बढ़त लेकर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 253.31 अंक यानी 0.34 फीसदी की हल्की बढ़त के साथ 73,917.03 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 73,459.80 और 74,070.84 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी में भी 62.25 अंक यानी 0.28 फीसदी की मामूली बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 22,466.10 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 22,345.65 और 22,502.15 के रेंज में कारोबार हुआ।

यूएन ने 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाया

नईदिल्ली। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने साल 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.9 फीसदी कर दिया है। इससे पहले यूएन ने जनवरी में 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीले निजी उपभोग के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को '2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं' पर रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र के नीति प्रभाग में वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद राशिद ने बृहस्पतिवार को यहां पत्रकारों कहा, ''भारत को अन्य पश्चिमी स्रोतों से भारत में आने वाले अधिक निवेश से भी लाभ हो रहा है, क्योंकि चीन में कम से कम विदेशी निवेश जा रहा है।

भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी लाने की जरूरत

नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाने की जरूरत है। सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में भारतीय उद्योग के प्रमुखों को संबोधित करते हुए मंत्री ने उत्पाद निर्माण और नीति समर्थन में अधिक परिष्करण हासिल करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। सीतारमण ने कहा, '' मैं कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई इस सलाह के विपरीत कुछ रेखांकित करना चाहती हूं कि भारत को अब विनिर्माण पर ध्यान नहीं देना चाहिए या विनिर्माण में तेजी नहीं लानी चाहिए। मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहती हूं कि विनिर्माण में वृद्धि होनी चाहिए। भारत को नीतियों की मदद से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी (विनिर्माण) हिस्सेदारी भी बढ़ानी चाहिए।''

आईआईएफएल सिक्योरिटीज का नेट प्रॉफिट हुआ दोगुना

नईदिल्ली। आईआईएफएल सिक्योरिटीज का जनवरी-मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ दोगुना होकर 180.4 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का पिछले साल समान अवधि में मुनाफा 86.4 करोड़ रुपये था। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने एक बयान में कहा, वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 74% बढ़कर 704.4 करोड़ रुपये हो गई। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के चेयरमैन वेंकटरमन ने कहा, हमने अपने सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि देखी। हमारी संस्थागत ब्रोकिंग और निवेश बैंकिंग फ्रेंचाइजी ने शानदार परिचालन प्रदर्शन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति में काफी सुधार किया है। समूचे वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 512.1 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। कुल आय 63% की वृद्धि के साथ 2,231.3 करोड़ रुपये रही।

अर्थव्यवस्था का सहारा बने प्रवासी भारतीय

डॉ जयंती लाल भण्डारी

हाल ही में यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी के द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्रवासियों के द्वारा वर्ष 2022 में भेजा गया रेमिटेंस दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है और यह 111 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि प्रवासी भारतीयों के परिश्रम, उनकी दक्षता और उनके मातृभूमि के प्रति स्नेह को भी रेखांकित करती है।

यह कोई छोटी बात नहीं है कि दुनिया के कोने-कोने में भारतवंशी और प्रवासी भारतीयों की राजनीतिक, आर्थिक और कारोबारी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती ऊंचाइयां भारत के तेज विकास के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो गई हैं। दुनिया के अनेक देशों में कई भारतवंशी राजनेता अपने-अपने देशों को आगे बढ़ाते हुए विश्व के समक्ष भारत के चमकते हुए चेहरे हैं साथ ही ये विश्व मंच पर भारत के हितों के हिमायती भी हैं और हरसंभव तरीके से भारत के विकास में अपना अहम योगदान देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इतना ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों में राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचने के साथ-साथ भारतवंशी व प्रवासी भारतीय वैश्विक आर्थिक व वित्तीय संस्थानों आईटी, कम्प्यूटर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त आदि के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। दुनिया के कोने-कोने में विस्तारित भारतीय प्रवासियों का मत है कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक मंचों पर जिस तरह भारत की सफलताओं का परचम फहराया है, उससे दुनिया में इंडिया फिलांथ्रोपी अलायन्स (आईपीए) जैसे भारत हितैषी संगठन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

इंडियास्पोरा भारत के विकास में अहम योगदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में अमेरिका में स्थापित एक ऐसी गैर-लाभकारी संस्था है, जो करीब 20 देशों में सक्रिय रूप से मजबूती के साथ काम कर रही है। यह संगठन दुनियाभर के विभिन्न देशों के प्रवासी भारतीयों के लिए भी प्रेरणादायी बन गया है।इस संगठन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के बढ़ाए गए गौरव और प्रवासी भारतीयों के लिए किए गए विशेष प्रयासों से भारतवंशियों तथा प्रवासियों का भारत के लिए सहयोग और स्नेह लगातार बढ़ा है।

ऐसे में अब भारत के तेज विकास और भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के मद्देनजर भारतवंशियों व प्रवासियों द्वारा तन-मन धन से आगे सहयोग करने के संकल्प के अभियान को 'इंडियास्पोरा' द्वारा दुनियाभर में आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 को अभूतपूर्व सफलता दिलाने में प्रवासी भारतीयों की भी अहम भूमिका रही है।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। हम उम्मीद करें कि प्रवासी भारतीय अपने ज्ञान व कौशल की शक्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, वर्ष 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकेंगे।

4 जून को बीजेडी सरकार का एक्सपायरी डेट, 10 को ओडिशा में भाजपा सरकार: साय

रायपुर/बीरमित्रपुर/राजगांग पुर/सुंदरगढ़। ओडिशा में भाजपा ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें प्रदेशवासियों के हित के लिए बहुत कुछ है। भाजपा सरकार बनने पर यहाँ किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी, हमारी माताओं को पचास हजार रुपए का वाउचर मिलेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और बुनकरों को तीन हजार रूपया भत्ता मिलेगा। छोटा-मोटा काम करके अपना जीवन-यापन करने वाले लोगों को हमारी सरकार पचास रुपए का लोन देगी। ओडिशा की पच्चीस लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। यहाँ के पांच लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। यहां पंद्रह लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। इसलिए आने वाले चार जून को बीजेडी सरकार का एक्सपायरी डेट है और दस जून को यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज लगातार दूसरे दिन ओडिशा में तीन जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सुंदरगढ़ लोकसभा के बीरमित्रपुर, राजगांगपुर और सुंदरगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे।

डबल इंजन की सरकार मतलब - विकास- श्री साय ने ओडिशा की जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाएं और कहा कि मात्र 4 महीने में उनकी सरकार ने मोदी की गारंटी के बड़े-बड़े वादे पूरे किये हैं। शपथ लेने के दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद कर 3100 रूपए क्विंटल धान की कीमत दी और अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए 24.72 लाख किसानों को देने का काम किया। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने के पहले सप्ताह में 70 लाख से ज्यादा माताओं-बहनों के खातों में एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि देने की बात भी कही। ओडिशा की जनता से भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाने का आग्रह किया।

मोदी का कोई विकल्प नहीं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए विष्णु देव साय ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का चुनाव है। मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए गरीबों की पीड़ा उन्हें अच्छे से पता है। नरेंद्र मोदी जी देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता करते हैं। प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने गरीबों को गैस सिलेंडर देने, पक्के घर देने, स्वच्छ पानी, मुफ्त उपचार की सुविधा, बैंक खाता खुलवाने से लेकर शौचालय बनवाने का काम किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाने, जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के साथ देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का काम पिछले दस साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। श्री साय ने कहा कि मोदी जी ने पिछले दस वर्षों में देश को आर्थिक क्षेत्र में जो ग्यारहवें नंबर पर था उसे पांचवें नंबर पर लाकर खड़ा किया। आने वाले पांच वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। इसलिए हमें तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने तूफानी दौरे के अंतर्गत आज ओडिशा के सुंदरगढ़ लोकसभा में तीन जनसभाओं को सम्बोधित किया। इससे पहले कल उन्होंने सुंदरगढ़ के बालीसंकरा में सभा लेकर जुएल ओरांव के लिए वोट मांगे। श्री साय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब जुएल भाई आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री थे, तब उन्होंने मुझे मेरे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत पैसा दिया। जुएल भाई कहते थे कि जितना पैसा चाहिए तुम ले जाओ विष्णु, आदिवासियों का विकास उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने जनता से जुएल ओरांव को छठवीं बार जिताने का आग्रह किया। जिससे कि सुंदरगढ़ लोकसभा के विकास को और अधिक गति मिले।

विकास से कोसो दूर है ओडिशा

बीजेडी सरकार को घेरते हुए सीएम साय ने कहा कि यहां चौबीस वर्षों से नवीन पटनायक की सरकार है, मगर दुर्भाग्य कि चौबीस वर्षों में वे ओड़िया नहीं सीख पाए। तो वो ओडिशा के लोगों की तकलीफ को कैसे समझेंगे। लोग कहते हैं कि ओडिशा की सरकार को नवीन बाबू नहीं कोई दूसरा आदमी चला रहा है। यह बड़ी विचित्र बात है। उन्होंने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम आदमी को न मिलने का आरोप लगाया और कहा बीजेडी सरकार ने केंद्र की योजना का नाम बदलकर बीजू स्वास्थ्य योजना कर दिया। लेकिन राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका लाभ गरीबों को नहीं मिलता है। यह दुर्भाग्यजनक है।

ओडिशा में भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण- मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज ओडिशा के सुंदरगढ़ लोकसभा के अंतर्गत जामपाली में जनसभा को संबोधित किया। सभा के पश्चात पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा में आज हमारा पांचवा दिन है और बीते दिन नवरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बरगढ़, बलांगीर सहित कई लोकसभाओं में जाना हुआ है। ओडिशा में भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। इस बार परिवर्तन अवश्य होगा। प्रदेश में 25 साल की बीजेडी सरकार को यहां की जनता उखाड़ के फेंकने वाली है और डबल इंजन की सरकार बनाने वाली है। सभी जानते हैं कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो सबको लगता है कि इस बार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास तेजी से होगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के एक साथ प्रचार करने के सवाल पर श्री साय ने कहा कि चुनाव प्रचार तो सभी करेंगे लेकिन आज कांग्रेस की क्या दुर्गति है वो पूरा देश देख रहा है। आज देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।

: छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने झारखंड में ली कार्यकर्ताओं की बैठक

प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के गोमिया, बेरमो व बाघमारा विधानसभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विजय झारखंड के संकल्प को और मजबूत करने के लिए जरूरी टिप्स दिए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक मतदान करवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, गरीब, आदिवासी और पिछड़े तथा युवा और महिलाओं के कल्याण को गति देते हुए विकसित भारत बनेगा। यह भाजपा को प्रचंड बहुमत से ही संभव होगा। उल्लेखनीय है कि झारखंड में इन दिनों छत्तीसगढ़ भाजपा के कई सांसद, विधायक और पदाधिकारी चुनावी कमान संभाले हुए हैं।

श्रीमती ज्योति परमाले को विद्यावाचस्पति की उपाधि

रायपुर। शंकर शिव नारायण साहित्य, ग्राम बलिवन सागर, गोपाल गंज बिहार (भारत) थावे विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में उप कुलसचिव डा. गिरधारी लाल अग्रवाल व्दारा श्रीमती ज्योति परमाले को उनकी सदीर्घ हिन्दी सेवा. सारस्वत साधना कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियो. शोधकार्य तथा राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के आधार पर इस विदयापीठ की अकादमिक परिषद् की अनुशंसा पर विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई ।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव संबलपुर लोकसभा क्षेत्र के रेंगाली में आयोजित विजय संकल्प रैली में हुए सम्मिलित

ओडिशा में डबल ईंजन की सरकार बनना तयः साव

रायपुर/संबलपुर। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने ओडिशा में लगातार चुनावी सभाएं कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाया है। श्री साव गांव गांव में। सभाएं और बैठक कर जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, शुक्रवार को उन्होंने संबलपुर लोकसभा क्षेत्र के रेंगाली विधानसभा के सानाटिकरा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया।

रैली में श्री साव ने कहा कि, एक गरीब मां का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। उन्होंने 10 वर्षों में गांव, गरीब और किसानों के लिए काम किया है। कोरोना काल में गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया, और आज तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। सभी देशवासियों को फ्री में कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगवाया, क्योंकि वो गरीब मां का बेटा है। लोगों के दुख दर्द को समझता है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, मोदी ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं को मासिक एक हजार रुपए देने की गारंटी दी थी। आज महिलाओं को तीन किश्त मिल चुकी हैं। किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी की जा रही है।

यहां ओडिशा में भी मोदी ने सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को दो साल में 50 हजार रुपए का कार्ड देने का वादा किया है, जिसे दो साल में खर्च कर सकेंगे। किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी की जाएगी।

साव ने कहा कि,मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, संबलपुर लोकसभा से केंद्रीय मंत्री और भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान और रेंगाली विधानसभा से नौरी नायक को जनता का भरपूर प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है।

केंद्र में मोदी की और ओडिशा में भाजपा की सरकार होने पर राज्य में तेजी से विकास होगा।

सुभद्रा योजना से मातृशक्ति और मजबूत होगी: लता उसेंडी

रायपुर। भाजपा ओडिसा प्रदेश की सह प्रभारी व वरिष्ठ विधायक लता उसेंडी ने भुवनेश्वर में चुनावी अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सुभद्रा योजना से ओडिसा प्रदेश की मातृशक्ति और मजबूत होंगी।यहाँ प्रदेश में नवीन पटनायक सरकार ने महिलाओं को छला है। जिसके के कारण महिलाओं में काफी आक्रोश है। यही कारण है अब पूरे ओडिसा में बदलाव की बयार है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

झारखंड में पिता-पुत्र के भ्रष्टाचार में लिपटी पॉलिटिक्स समाप्त होगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने कहा है कि झारखंड में भाजपा को लेकर जिस तरह मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे यह तो तय है कि इस बार के चुनाव से राज्य को पिता-पुत्र की पॉलिटिक्स से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के संसाधनों की जैसे खुली लूट मचाई है, उससे जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। भूपेंद्र सवन्नी इन दिनों झारखंड के प्रवास हैं। यहां अलग-अलग चुनाव प्रचार कार्यक्रम एवं जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट करने का आह्वान कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, यह लोकसभा चुनाव सिर्फ विकसित भारत के संकल्प का चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और लालफिताशाही से मुक्ति दिलाने का भी चुनाव है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अब चुनाव में अपनी हार तय मानकर नये बहाने खोजने लगी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा विगत दस साल में जनकल्याण की जितनी योजनाएं संचालित की गई हैं, उससे गरीब, पिछड़े, आदिवासी, महिलाओं, युवा का सबसे अधिक कल्याण हुआ है. आज गरीब किसान और आदिवासी आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होकर सामने आए हैं. तीसरी बार देश की बागडोर संभालकर नरेंद्र मोदी जनकल्याण के कार्यों को और गति देंगे।

विकास से कोसों दूर है ओडिसाः राजेश मूणत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व विधायक राजेश मूणत ने पुरी लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा के समर्थन में चुनावी जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेते कहा कि जिस गति से ओड़िसा का विकास होना था वह नहीं हुआ. इसके लिए नवीन सरकार जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, जो सपना बीजू जनता दल ने यहां की जनता को दिखाया था वह सपना ही रह गया है। अब सही वक्त आ गया है कि उत्तम ओडिसा के लिये भाजपा को चुना जाए. भाजपा ही प्रदेश को एक मजबूत विकल्प दे सकती है. यहां की जनता पूरे मनोयोग से भाजपा के साथ है.

भाजपा ही बदलेगी तकदीर और तस्वीरः शिवरतन शर्मा

छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने संबलपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में चुनाव अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ही ओडिसा की तस्वीर बदल सकती हैं। इसलिये भाजपा को लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में प्रचण्ड बहुमत से विजयी बनाएं. शिवरतन शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिसा के विकास के लिये संवेदनशील नहीं रहे हैं।

एक हाइवा और चैन माउंटेन मशीन सहित, भण्डारित रेत जब्त

रायपुर। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में गौण खनिजों विशेषकर रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण के मामले में जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर श्री धर्मेश साहू के मार्गदर्शन में जिले के खनिज अधिकारियों की टीम गौण खनिजों के उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन के मामले में जब्ती और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कर रही है। कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा गौण खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन के मामले में कार्रवाई का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। जिले के सिंघनपुर गांव में रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण के मामले में खनिज विभाग की टीम द्वारा औचक कार्रवाई कर एक हाइवा, जेसीबी और बड़ी मात्रा रेत की जब्ती की गई है। जिले के कोसीर क्षेत्र के सिंघनपुर में रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण के मामले में खनिज अधिकारियों की टीम ने मौके पर दबिश देकर एक हाइवा तथा बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भण्डारित रेत जब्त की। खनिज अधिकारी हीरादास भारद्वाज ने बताया कि अधिकारियों की टीम ने सिंघनपुर में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से बड़ी मात्रा में भण्डारित रेत का मामला पकड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि भण्डारित रेत लगभग 80 से 100 हाइवा है, जिसे सिंघनपुर के रहने वाले कृष्णा राजपूत द्वारा भण्डारित किया गया है।

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल-योजनाओं की निगरानी में होगी आसानी

रायपुर। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल (सी.एम.डेशबोर्ड) के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक दिवसीय डिजाईन वर्कशाप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिव स्तरीय अधिकारियों, विभागीय नोडल अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ को अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में क्रियान्वयन किए जाने वाले सभी केन्द्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं, जन हित में लिए गए प्रमुख निर्णयों, दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। कार्यशाला में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (टी.आर.आई.के.) डॉ. आंद्रे नोगवीरा और उनकी टीम ने पोर्टल के विकास संबंधी तकनीकी विषयों की जानकारी दी।

रिश्वत मामलाः नगर एवं ग्राम निवेश के सहायक संचालक मानचित्रकार निलंबित

रायपुर। संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सहायक संचालक (सर्वे) बालकृष्ण चौहान एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से जारी आदेश अनुसार इन दोनों के विरूद्ध रिश्वत लेने के अपराध में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया जाकर अपचारी अधिकारी के विरूद्ध धारा-7, पी.सी. एक्ट, 1988 संशोधित 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। अतएव बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार का मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर निर्धारित किया जाता है।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विद्यार्थियों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं

कड़ी मेहनत और अनुशासन से प्रयास विद्यालय के बच्चों को मिली शानदार सफलता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं के कड़ी मेहनत और अनुशासन से शानदार सफलता मिली है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हाल ही घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों में प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चों को एक बार फिर शानदार सफलता मिली है। प्रयास विद्यालय में 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 99.3 प्रतिशत एवं 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 97.22 प्रतिशत रहा है। इनमें 10वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 96.45 एवं 12वीं में 82.02 प्रतिशत रहा है। इस वर्ष का परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में काफी अच्छा है। गत वर्ष 10वीं में 90.70 प्रतिशत और 12वीं में 79.38 फीसदी रहा था। प्रदेश के प्रयास विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा और सचिव श्री नरेन्द्र दुग्गा ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब तक प्रयास आवासीय विद्यालय के 116 विद्यार्थी आईआईटी व समकक्ष में, 328 विद्यार्थी एनआईटी व समकक्ष में, 940 विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेज में एवं 52 विद्यार्थी एम.बी.बी.एस. में चयनित हुए हैं। इसके अलावा सीए, सीएस, सीएमए में 29 तथा क्लैट में 04 विद्यार्थी को सफलता मिल चुकी है।

10वीं में 07 बच्चों ने बनाया मेरिट में स्थान- आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष घोषित परीक्षा परिणामों में प्रयास के 07 विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान बनाया है। मेरिट में आने वाले छात्र-छात्रों में प्रयास आवासीय विद्यालय, कांकेर के 04 विद्यार्थी- श्री मयंक कोर्राम, कुमारी पायल अधिकारी, कुमारी वर्षा साहू और कुमारी मल्लिका मरकाम शामिल हैं। इसी प्रकार प्रयास विद्यालय दुर्ग, जशपुर एवं कन्या प्रयास विद्यालय रायपुर से एक-एक विद्यार्थी- क्रमशः कुमारी आर्या कश्यप, आयुष साहू और कुमारी बॉबी मिंज ने मेरिट में स्थान बनाने में सफल हुए है।

ऑनलाईन आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से अशासकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी एवं आबंटन 20 से

रायपुर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयो में आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन, भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण में लॉटरी एवं आबंटन की कार्यवाही 20 मई से 30 मई तक की जाएगी और उसके बाद स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया 1 जून से 30 जून तक होगी। आर.टी.ई. के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही के लिए निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार द्वितीय चरण के लिए नवीन स्कूल पंजीयन (आवेदन) और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कार्य 15 जून से 30 जून तक किया जाएगा। छात्र पंजीयन (आवेदन) 1 जुलाई से 8 जुलाई तक होगा। इसके बाद नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 9 जुलाई से 15 जुलाई तक की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन का कार्य 17 जुलाई से 20 जुलाई तक किया जाएगा। इसके बाद स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया 22 जुलाई से 31 जुलाई तक की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाईन दावा प्रक्रिया 1 अगस्त से 30 अगस्त तक किया जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों, संभागीय शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.